CNEWS सिटी चीफ

वर्ष-15, अंक-108
पृष्ठ-8 मूल्य 2 रूपया

आज का विचार

उम्मीद रखना ऊँची उड़ानों की छांव में ना खो जाना तुम, ठोकरों से सीख लेना ज़रा सफर जारी रखना तुम।

सिटी चीफ

सम्पूर्ण भारत मे चर्चित हिन्दी अखबार

CITYCHIEFSENDMENEWS@GMAIL.COM

इंदौर, मंगलवार 23 जुलाई 2024

सिंगल कॉलम

नीट पेपर लीक मामले की जांच में आईआईटी दिल्ली भी शामिल

नई दिल्ली। *नीट-यूजी पेपर लीक मामले की जांच में अब सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली को भी शामिल कर लिया है। अदालत ने सोमवार को आदेश दिया कि आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर तीन एक्सपर्ट्स की एक कमेटी का गठन करें। यह कमेटी परीक्षा में आए एक सवाल के सही जवाब पर राय दे। दरअसल एक ऐसे सवाल का मसला भी उठा है, जिसके दो सही उत्तर माने जा रहे हैं। ऐसे में अदालत ने एक्सपर्ट्स की एक कमेटी से ही इस पर जवाब मांग लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मंगलवार को दोपहर 12 बजे तक जवाब मांगा है। इसके साथ ही कल तक के लिए सुनवाई भी टाल दी है। सोमवार को अदालत में दिलचस्प सुनवाई देखने को मिली। कोर्ट में याचियों के वकील नरेंद्र हुड्डा ने दलील दी कि एनसीईआरटी के एक सवाल के चलते 44 लोगों को टॉप रैंक मिल गई है। इस सवाल के दो जवाब सही माने जा रहे हैं। ऐसे में किसी एक जवाब को ही सही माना जाए और उस पर स्पष्टता होनी चाहिए। इसी तर्क पर अदालत ने दिल्ली आईआईटी को एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाने को कहा है। यह सवाल फिजिक्स से जुड़ा था। सुनवाई के दौरान वकील हुड्डा ने कहा कि पेपर लीक वॉट्सऐप के जरिए हुआ है। इसलिए यह बिहार या झारखंड तक ही सीमित रहा, ऐसा नहीं माना जा सकता। उन्होंने सॉल्वर्स को राजस्थान से ले जाया गया। वॉट्सऐप पर पेपर लीक हुआ। इसलिए इतनी गहरी साजिश है तो फिर यकीन करना मुश्किल है कि पेपर लीक पटना तक ही सीमित रहा हो। उन्होंने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट दोबारा से एग्जाम नहीं कराना चाहता तो कम से कम क्वॉलिफाई करने वाले लोगों से दोबारा पेपर लिया जाए। वहीं एनटीए की ओर से पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने माना कि देश के 8 सेंटरों पर गलत प्रश्न पत्र बंट गया। लेकिन दोनों का लेवल एक जैसा ही था। ऐसे छात्रों की संख्या भी 3000 के करीब ही थी। ऐसे में एनटीए का यह फैसला सही है कि इन छात्रों को भी बने रहने दिया जाए। वहीं एडवोकेट हुड्डा ने कहा कि 650 से ज्यादा नंबक 241 छात्रों को मिले। इसके अलावा 241 लोगों को 550 नंबर या उससे ज्यादा मिल गए।*

सिर्फ चार जोड़ों को निभानी थी शादी, हजारों जोड़ों ने विवाद की ठानी!

देहरादून। *शादी बाद लड़ाई-झगड़े होने पर भले जीवनभर कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगा लेंगे, लेकिन शादी से पहले काउंसलिंग कराने नहीं जाएंगे...इस सोच से समाज को उबारने के लिए राज्य महिला आयोग ने आठ साल पहले विवाह पूर्व काउंसलिंग की जोर-शोर से पहल की थी, लेकिन अफसोस कि आज तक सिर्फ चार जोड़े ही काउंसलिंग के लिए आयोग के दफ्तर पहुंचे। विवाह पूर्व काउंसलिंग को नजरंदाज करने का नतीजा या आंकड़े ऐसे हैं कि आयोग के सामने हर साल दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न और घरेलू हिंसा की 700 से 1000 शिकायतें पहुंच रही हैं। साथ ही दोनों पक्षों के परिजन आयोग से लेकर पुलिस स्टेशन और अदालत के चक्कर लगा रहे हैं। इसलिए महिला आयोग की कोशिश है कि लोगों को समझाया जाए कि शादी के बाद कोर्ट में एक-दूसरे के खिलाफ लड़ने से बेहतर है कि शादी से पहले काउंसलिंग के जरिए एक-दूसरे को समझा जाए। राज्य महिला आयोग का मानना है कि कई बार रिश्तों की खटास में बातचीत मिठास का काम करती है और गृहस्थी उजड़ने से बच जाती है। यदि लोग आयोग के कार्यालय नहीं आ सकते, तो उनके पास काउंसलिंग के दूसरे विकल्प भी हैं। आयोग की ही सलाह है कि लोग चाहें तो अपने नजदीक में ग्राम प्रधान, जिले के सदस्य, पारिवारिक मामलों के वकील, एनजीओ पदाधिकारी के साथ भी आपसी सामंजस्य से विवाह पूर्व काउंसिलिंग करवा सकते हैं। महिला आयोग कई मंचों से लोगों को जागरूक कर रहा है कि विवाह पूर्व काउंसलिंग करवाएं। इससे युवा पीढ़ी को उचित मार्गदर्शन मिलेगा। हिंसा और मानसिक उत्पीड़न के मामलों में कमी आएगी। आर्थिक मोर्चे पर सामंजस्य रहेगा और आमने-सामने बैठने से धोखाधड़ी की आशंका भी कम रहती है।*

मोदी 3.0 का पहला बजट : आम बजट में सरकार ने खोला खजाना...

छोटे कारोबारियों को बिना गारंटी लोन

- 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री
- बिहार को 3 एक्सप्रेस वे की सौगात, कैंसर की तीन दवाएं सस्ती हुई
- मुद्रा लोन अब 20 लाख रुपए
- कस्टम ड्यूटी घटने से मोबाइल होगा सस्ता, बिहार को 41 और आंध्र को 15 हजार करोड़ का पैकेज
- पीएम आवास योजना में 3 करोड़ घर बनेंगे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। यह उनका लगातार सातवां बजट है। केंद्रीय मंत्रीमंडल की मंजूरी के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट संबोधन शुरू किया। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट में गरीब, महिला, किसान और युवाओं पर फोकस किया गया है। जट भाषण से स्पष्ट है कि सरकार का फोकस रोजगार सृजन पर है। इसके लिए तीन योजनाओं का एलान किया गया है। पीएम आवास योजना का विस्तार किया गया है। मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाई गई है।

पहली नौकरी वालों के लिए: 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी।

एजुकेशन लोन के लिए: जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3 परसेंट तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे।

बिहार और आंध्रप्रदेश के लिए: आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ और बिहार को 41 हजार करोड़ रुपए की मदद। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल,ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम।

किसान के लिए: 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।

युवाओं के लिए: मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए। 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वादा।

महिलाओं और लड़कियों के लिए: महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान।

सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना: 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री।

मोबाइल फोन सस्ते होंगे: मोबाइल फोन और पार्टस् पर GST कम किया। मोबाइल सस्ते होंगे। एक्सपोर्ट के लिए बनने वाले लेदर गुड्स को जीएसटी से छूट।

न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़कर 75 हजार हुआ

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार किया गया। इसके अलावा 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 7 लाख रुपए तक 5 फीसदी, 7 से 10 लाख रुपए तक 10 फीसदी, 10 से 12 लाख रुपए तक 15 फीसदी। 12 से 15 लाख तक 20 फीसदी। 15 लाख से ज्यादा की सैलरी पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा।

नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ग्रामीण और शहरी इलाके में नए बिल्डिंग बॉयलाज तैयार होंगे। जमीन रजिस्ट्री के डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। लैंड रिकॉर्ड को जीआईए सिस्टम से जोड़ा जाएगा। मजदूरों के लिए ई श्रम पोर्टल शुरू किया गया है, जो वन स्टॉप सेंटर की तरह काम करेगा। श्रम सुविधा एवं समाधान पोर्टल इंडस्ट्री और ट्रेड के बीच आने वाली परेशानियों को दूर करेगा। हस्क वात्सल्य अकाउंट्स की शुरुआत की जा रही है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं।

बजट एस्टीमेट : 32.07 **लाख करोड़** राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9 फीसदी रहा है। सरकार 2026-27 में इसे कम करने की कोशिश करेगी।

टूरिज्म: निर्मला सीतारमण ने कहा कि काशी की तर्ज पर गया में विष्णु पथ मंदिर कॉरिडोर और बोध गया में महाबोधि कॉरिडोर डेवलप होंगे। ताकि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। ओडिशा में भी मंदिरों का डेवलपमेंट किया जाएगा। राजगीर बड़ा टूरिस्ट सेंटर बनेगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर: वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में लोन के लिए 1.5 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 5 हजार नए गांवों को जोड़ा जाएगा। बिहार में बाढ़ नियंत्रण स्ट्रक्चर के लिए 11 हजार 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के कारण हर साल बाढ़ आती है। हम उसके लिए भी बाढ़ नियंत्रण स्ट्रक्चर का प्रावधान कर रहे हैं। उत्तराखंड भूस्खलन के कारण आपात स्थिति का सामना करता है। उसे भी आर्थिक मदद देंगे।

आवास: निर्मला सीतारमण ने कहा कि शहरी आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। 100 बड़े शहरों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति पर काम जारी है शहरी आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। 1 करोड़ मकान बनाए जाएंगे। 100 बड़े शहरों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति पर काम जारी है।

एनर्जी सिक्योरिटी : निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए सरकार ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत रूफ टॉप सोलर सेटअप किए जा रहे हैं। इसके लिए सब्सिडी का प्रावधान किया जा चुका है।

एमएसएमई: तरुण कैटेगरी में मुद्रा लोन का दायरा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया जा रहा है। 3 फीसदी ब्याज पर छात्रों को लोन मिलेगा। एमएसएमई क्लस्टर बढ़ाने पर सरकार का जोर है। 50 मल्टी फूड प्रोडक्ट के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। ई कॉमर्स और एक्सपोर्ट हब पीपीपी मॉडल पर बनाए जाएंगे। हमारी सरकार 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान कराएगी। ताकि वे 12 महीने में रोजगार की व्यवहारिकता को समझें। उन्हें कंपनियों के सीएसआर फंड से 5000 रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड भी दिया जाएगा।

रोजगार और कौशल विकास: ईपीएफओ के जरिए कुछ नई इंसेंटिव स्कीम शुरू की गई हैं। डीबीटी के जरिए 210 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा। महिला कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सरकार नई योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना में 20 लाख युवाओं को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी।

पीएम आवास योजना- 3 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे।

प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसमें 63 हजार गांव कवर होंगे। 2.66 करोड़ रुपए रूरल डेवलपमेंट के लिए आवंटित कर रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट में हम 4.1 करोड़ युवाओं के रोजगार, कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान कर रहे हैं। इस साल 1.48 लाख करोड़ रुपए पहले ही दे चुके हैं। इस बजट में 9 प्राथमिकताएं हैं। कृषि विकास, रोजगार और कौशल, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेक्सट जनरेशन रिफॉर्म। सरकार सबके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मिडिल क्लास और रोजगार पर फोकस है।

नेमप्लेट विवाद पर यूपी सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर लगाई रोक, तीन राज्य सरकारों को भेजा नोटिस

दुकान मालिकों को नाम बताने की जरूरत नहीं

नई दिल्ली। कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटलों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने यूपी प्रशासन के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं। दुकान मालिकों को नाम बताने की जरूरत नहीं है।

दुकानदारों को सिर्फ खाने के प्रकार बताने की जरूरत है। मतलब यह कि दुकान पर सिर्फ लिखे होने की जरूरत है कि वहां मांसाहारी खाना मिल रहा है या शाकाहारी खाना। कोर्ट ने इस मामले में अदालत ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट में एनजीओ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स द्वारा याचिका दाखिल की गई। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसे अभी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

इस तरह चली सुनवाई.....

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या यह प्रेस स्टेटमेंट था या औपचारिक आदेश था कि इन्हें प्रदर्शित किया जाना चाहिए? याचिकाकताओं के वकील ने जवाब दिया कि पहले एक प्रेस स्टेटमेंट था और फिर लोगों में आक्रोश था और वे कहते हैं कि यह स्वैच्छिक है लेकिन वे इसे सख्ती से लागू कर रहे हैं। वकील ने कहा कि कोई औपचारिक आदेश नहीं है, बल्कि पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह एक छद्म आदेश है। एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने कहा,अधिकांश लोग बहुत गरीब सब्जी और चाय की दुकान के मालिक हैं और इस तरह के आर्थिक बहिष्कार के अधीन होने पर उनकी आर्थिक मृत्यु हो जाएगी।

अभिषेक मनु सिंघवी ने दी यह दलील

अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा कि बहुत सारे शुद्ध शाकाहारी रेस्तरां हैं जो हिंदुओं द्वारा चलाए जाते हैं और उनमें मुस्लिम कर्मचारी भी हो सकते हैं, क्या मैं कह सकता हूं कि मैं वहां जाकर नहीं खाऊंगा क्योंकि खाना किसी न किसी तरह से मुस्लिमों या दलितों द्वारा छुआ जाता है? सिंघवी कहते हैं कि निर्देश में कहा गया है स्वेच्छा से (इच्छा से) लेकिन स्वेच्छा कहां है? मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी भोजनालयों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को इसे पूरे राज्य में बढ़ा दिया है। इस सप्ताह की शुरूआत में मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा आदेश जारी किया गया था कि कांवड़ यात्रा वाले रूट पर दुकानदार अपनी दुकान पर नेमप्लेट लगाएं ताकि कावड़ियां को पता चले कि दुकानदार का नाम क्या है।

मध्य प्रदेश के सागर में दुर्घटना

इंदौर से आ रही बस पलटी... 15 यात्री हुए घायल

सागर। सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र के भापेल के पास सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात इंदौर से सागर की ओर जा रही सवारियों से भरी बस अचानक पलट गई। हादसे में करीब 15 यात्री घायल हुए हैं। चार यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं, जो जिला अस्पताल में इलाजरत हैं।जानकारी के अनुसार इंदौर से रीवा तक चलने वाली बस क्रमांक एमपी 19 पी 2856 सागर की ओर आते समय रात करीब डेढ़ बजे भापेल में पुल के पास अनियंत्रित अचानक पलट गई। दलपतपुर चौकी क्षेत्र के खटोरा कलां निवासी प्रद्युम पिता भैयालाल अहिरवार ने बताया कि बस चालक तेज व लापरवाही पूर्वक चला रहा था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। हादसे के समय बस में तीस से अधिक यात्री सवार थे। जानकारी के अनुसार इंदौर से रीवा तक चलने वाली बस क्रमांक एमपी 19 पी 2856 सागर की ओर आते समय रात करीब डेढ़ बजे भापेल में पुल के पास अनियंत्रित अचानक पलट गई। दलपतपुर चौकी क्षेत्र के खटोरा कलां निवासी प्रद्युम पिता भैयालाल अहिरवार ने बताया कि बस चालक तेज व लापरवाही पूर्वक चला रहा था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। हादसे के समय बस में तीस से अधिक यात्री सवार थे। बस के पलटते ही गहरी नींद में सो रहे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। जैसे-तैसे यात्रियों ने बस में अपने आप को संभाला। हादसे की सूचना पुलिस और एंबुलेंस को दी गई। मौके पर मोतीनगर से एएसआई राकेश भट्ट, प्रधान आरक्षक अनिल प्रभाकर सहित अन्य पुलिस कर्मी पहुंचे और घायलों का बमुश्किल बस से बाहर निकाला। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। घायलों को बस से निकालकर 108 एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बस में अधिकांश यात्री मजदूर थे, जो इंदौर, भोपाल से मजदूरी कर सीधी बैढ़न तक जा रहे थे। हादसे में 23 वर्षीय प्रद्युम को दाहिने कंधे और उसकी पत्नी प्रतिमा को दाहिने घुटने, कमर में चोटें आई हैं। सागर जिले में यात्री बसों के दुर्घटनाग्रस्त होने की 15 दिन में यह पांचवीं घटना है। इसके पूर्व गढ़ाकोटा मंडी, गढ़ाकोटा के भूरेबाबा मजार के पास, बांदरी फोरलेन पर यात्री बसें हादसे का शिकार हो चुकी है, जिसमें कई यात्री घायल हुए थे।

इंदौर में बड़ी ठगी... पीतल की ज्वेलरी पर चढ़ाई सोने की परत

गिरवी रखकर ले गए सवा दो करोड़ रुपये

प्रदीप चौधरी | सिटी चीफ |

इंदौर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रिटायर्ड अफसर से ठगी का मामला सामने आया है। एक ज्वेलर ने सोने की परत चढ़ी पीतल की ज्वेलरी उन्हें देकर सवा दो करोड़ रुपये ले लिए। बुजुर्ग को जब ज्वेलरी नकली होने का पता चला तो उन्होंने पुलिस से इसकी शिकायत की। पुलिस ने आरोपित को ज्वेलर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। ज्वेलर ने पहले असली सोना गिरवी रखवाया। इसके बाद उसने बुजुर्ग का विश्वास जीत लिया। भरोसा कर बुजुर्ग ने सोना चेक नहीं करवाया। बिजली विभाग के रिटायर्ड अफसर को ज्वेलर्स ने सवा दो करोड़ रुपये की चपत लगा दी। आरोपितों ने सोने की परत चढ़े पीतल के आभूषण गिरवी रखे और करोड़ों रुपये ले लिए। पुलिस ने एक आरोपित को हिरासत में ले लिया है। ठगी का आंकड़ा बढ़ सकता है। नकली आभूषण जब्त कर लिए हैं। विजयनगर टीआई सीबी सिंह के मुताबिक स्कीम-54 निवासी दिनेश चंद्र चोपड़ा ने शिकायत दर्ज करवाई है। दिनेश बिजली विभाग से रिटायर हुए हैं। उनकी पत्नी शिक्षा विभाग में पदस्थ रही हैं। 76 वर्षीय चोपड़ा सोना गिरवी

रख कर ऋण देते थे।

शुरुआत में कम सोना गिरवी रख विश्वास जीता वर्ष 2014 में वीणा नगर निवासी दीपक राधाशरण अग्रवाल संपर्क में आया। दीपक की परदेशीपुरा में अन्नपूर्णा ज्वेलर्स के नाम से सोना चांदी की दुकान है। शुरुआत में दीपक ने कम मात्रा में सोना गिरवी रखा और रुपये लिए। दिनेश उस पर विश्वास करने लगे और सोना की जांच करवाना बंद कर दी। दीपक और उसकी पत्नी महिमा ज्यादा मात्रा में सोना रखने लगे। दोनों के बीच लाखों रुपये का लेनदेन होने लगा। वर्ष 2022 में दीपक का भाई अरुण अग्रवाल भी सोना गिरवी रख कर रुपये लेने का काम करने लगा।

ब्याज के लालच में रिश्तेदारों से रुपये लेकर देने लगे दिनेश ब्याज के लालच में रिश्तेदारों से रुपये लेकर आरोपितों को देने लगे। बदले में सोने के आभूषण गिरवी रखने लगे। 16 फरवरी को दिनेश ने रजत ज्वेलर्स से सोने की जांच करवाई तो ज्वेलर्स ने बताया आभूषण नकली हैं।

पुलिस ने हिरासत में लिया आरोपित अब तक 94 बार में करीब सवा दो करोड़ रुपये ले जा चुके थे। दोनों पक्षों ने बैठक की तो आरोपितों ने नकली आभूषण गिरवी रखना स्वीकार लिया। दिनेश ने उनका वीडियो बना लिया। ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली। रुपये न लौटाने पर डीसीपी जोन-2 अभिनय विश्वकर्मा को शिकायत की और शनिवार को एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने दिनेश को हिरासत में ले लिया है।

इंदौर में बनेंगी ग्रीन बिल्डिंग, नगर निगम और बिल्डर्स मिलकर करेंगे काम

इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल इंदौर चैप्टर ने ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में किया कार्यक्रम का आयोजन

इंदौर। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) इंदौर चैप्टर ने ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर, इंदौर में आवासीय विकास में सतत और हरित प्रथाओं को बढ़ाने पर एक सत्र की मेजबानी की। यह आयोजन आवासीय विकास में टिकाऊ प्रथाओं पर चर्चा करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए रियल एस्टेट और निर्माण क्षेत्रों के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाया।

सत्र का उद्घाटन शिवम वर्मा, आयुक्त इंदौर नगर निगम, संदीप श्रीवास्तव, अध्यक्ष क्रेडाई-इंदौर की उपस्थिति में हुआ। इसमें बताया गया कि जैसे-जैसे शहरीकरण तेज हो रहा है और आबादी बढ़ रही है, आवासीय विकास में हरित प्रथाओं को शामिल करने का महत्व सर्वोपरि हो गया है। आईजीबीसी इंदौर चैप्टर ने स्थायी समाधानों की आवश्यकता पर जोर दिया जो हमारे समुदायों के पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इंदौर नगर निगम के आयुक्त शिवम वर्मा (आईएएस) ने कहा कि इंदौर लगातार टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने में अग्रणी रहा है। उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेने पर प्रसन्नता व्यक्त की और आवासीय विकास, हरित घरों, भवनों और उत्पादों में सतत और हरित प्रथाओं पर इस मूल्यवान कार्यक्रम के आयोजन के लिए सीआईआई - आईजीबीसी इंदौर चैप्टर की सराहना की। उन्होंने नागरिकों की भलाई और सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निगम की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। वर्मा ने पूरे शहर और राज्य में हरित विकास को प्रोत्साहित करने वाली अनुकूल नीतियां स्थापित करने के लिए उठाए जा रहे सक्रिय उपायों पर प्रकाश डाला। उन्होंने निगम के दृढ़ विश्वास को बताते हुए निष्कर्ष निकाला कि हरित इमारतों के लिए प्रोत्साहन हितधारकों को मौजूदा और आगामी संरचनाओं में टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के लिए महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा क्रेडाई-इंदौर के अध्यक्ष संदीप श्रीवास्तव ने अपनी परियोजनाओं में टिकाऊ और हरित प्रथाओं को शामिल करने के लिए रियल एस्टेट क्षेत्र की प्रतिबद्धता बताई थी। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इंदौर नगर निगम अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) की पेशकश करके आईजीबीसी-प्रमाणित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करे। उनका मानना था कि यह पहल, बिल्डरों को टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करेगी, जिससे भूमि का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा और पर्यावरणीय पदचिह्न में कमी आएगी। उन्होंने 2030 तक सभी आगामी परियोजनाओं को हरित भवन बनाना सुनिश्चित करने के लिए आईजीबीसी के साथ क्रेडाई के समझौता ज्ञापन पर भी गर्व व्यक्त किया। आईजीबीसी इंदौर चैप्टर के अध्यक्ष विनोद बापना ने आवासीय विकास में हरित भवन सिद्धांतों को बढ़ावा देने के अपने लक्ष्य पर प्रकाश डाला था। उन्होंने मध्य प्रदेश के कुल 74 मिलियन वर्ग फुट में से 53 मिलियन वर्ग फुट से अधिक पंजीकृत हरित स्थान के साथ टिकाऊ निर्माण में इंदौर के नेतृत्व पर जोर दिया। बढ़ती आबादी को देखते हुए, बापना ने इस हरित पदचिह्न को दस गुना बढ़ाने की अपनी महत्वाकांक्षा व्यक्त की। सत्र का उद्देश्य डेवलपर्स और बिल्डरों को टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना था, जो अंततः एक हरित और अधिक लचीले इंदौर में योगदान देगा।

पुलिस को एक दिन बाद भी नहीं लगे युवती की हत्या के सुराग

पुलिस को रिश्तेदार और दोस्तों पर था शक, पूछताछ करके छोड़ा

इंदौर। इंदौर में युवती की सिर कुचलकर हत्या के मामले में पुलिस चौबीस घंटे बाद भी खाली हाथ है। पुलिस को उसके मौसा सहित दो दोस्तों पर शक था, लेकिन पूछताछ में इनके शामिल होने की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में युवती से रेप की पुष्टि भी नहीं की हुई है। पुलिस अब मुखबिरों के माध्यम से हत्या की जानकारी जुटाने में लगी है। पुलिस को एक सीसीटीवी हाथ लगा है, जिसमें वह अकेले जाती हुई दिख रही है। मामले में डीसीपी पंकज पांडे रविवार देर रात तक पूछताछ करते रहे। बाणगंगा इलाके में रविवार सुबह मनीषा नाम की युवती का शव मिला। उसकी सिर कुचलकर हत्या की गई। पुलिस को आशंका

थी कि हत्या के पहले उसका रेप किया गया। लेकिन शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। इस मामले में पुलिस को मनीषा के मौसा पर शक था। इसलिए उससे रविवार को पूछताछ की गई। लेकिन रेप या हत्या जैसी बात सामने नहीं आई। मौसा ने यह जरूर माना कि उसका और मनीषा का विवाद हुआ था। इस बीच पुलिस को सूचना मिली थी कि मनीषा दो दोस्तों महेश और एक अन्य के साथ घूमती और शराब पीती थी। पुलिस ने दोनों को भी थाने लाकर पूछताछ की। लेकिन उनसे भी हत्या या रेप के संबंध में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। इसके चलते पुलिस ने मौसा और दोनों दोस्तों को छोड़ दिया।

मौसा और उसके परिवार से हुआ था विवाद पुलिस को पूछताछ में पता चला कि मनीषा का मौसा और उसके परिवार से विवाद हुआ था। परिवार ने मारपीट कर उसका गला भी दबाया था। इसके बाद वह गुस्से में रिपोर्ट लिखाने की धमकी देकर घर से निकली थी। पर थाने नहीं पहुंची। पुलिस को घर से निकलने के बाद का सीसीटीवी भी मिला है। जिसमें वह अकेले जाते हुए दिखाई दे रही है। पुलिस को पता चला है कि मनीषा शराब और नशे की आदी थी। उसका कई लड़कों के साथ उठना बैठना था। पुलिस हरेक की जानकारी निकालने में जुटी है। इसके लिए मुखबिरों को एक्टिव किया गया है।

स्विमिंग पूल में छलांग के बाद युवक की मौत

इंदौर के युवक की मढ़ई के रिसॉर्ट में गई जान; हार्ट अटैक की आशंका

इंदौर। नर्मदापुरम जिले में मढ़ई स्थित एक रिसॉर्ट के स्विमिंग पूल में इंदौर के युवक की मौत हो गई। युवक ने पूल ने छलांग लगाई। वह 40 सेकंड तक ऊपर नहीं आया। दोस्तों ने उसे अचेत हालत में बाहर निकाला और सीपीआर भी दी। फिर उसे अस्पताल लेकर गए। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने हार्टअटैक की आशंका जताई है।

घटना 20 जुलाई की है। इसका सीसीटीवी फुटेज सोमवार को सामने आया। युवक अपने 5 दोस्तों के साथ घूमने के लिए मढ़ई पहुंचा था। चेक इन के 20 मिनट बाद ही घटना हो गई। पांच में से चार लोग फायर सेफ्टी इंजीनियर हैं, जबकि मृतक पीएससी की तैयारी कर रहा था। मृतक का नाम राहुल नागर (31) है। वह इंदौर के इमली बाजार का रहने वाला था। इंदौर के ही रहने वाले दीपक तिवारी, रजत जैन, हितेश निमाड़, राहुल नागर व शुभम जैन बचपन के दोस्त हैं।

25-30 सेकंड तक बाहर नहीं आया तो दोस्तों को हुई चिंता रजत जैन, दीपेश तिवारी ने बताया, हम 20 जुलाई को इंदौर से पचमढ़ी घूमने का प्लान कर कार से निकले थे। पचमढ़ी में रूम उपलब्ध नहीं होने से मढ़ई पहुंच गए। यहां ड्रीम व्यू रिजॉर्ट में दोपहर 2.20 बजे चेक इन किया। 10 मिनट बाद पांचों लोग नहाने के लिए स्विमिंग पूल पर पहुंच गए। यहां बैठकर एंजॉय करने लगे। इस दौरान दोपहर 2.47 बजे राहुल ने पूल में छलांग लगा दी।

करीब 25-30 सेकंड तक जब वह बाहर नहीं आया, तो हमें चिंता हुई। उसे पूल से बाहर निकाला। वह बेहोश हो गया था। उसे सीपीआर भी दिया। होश नहीं आने पर गाड़ी से सोहागपुर स्थित अस्पताल के लिए रवाना हुए। हड़बड़ाहट में निंभौरा में नहर के पास मोड़ पर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद लिफ्ट लेकर राहुल को सोहागपुर के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया।

दोस्त बोले- रिजॉर्ट प्रबंधन ने नहीं की मदद दीपेश तिवारी ने बताया, राहुल को पूल से निकालने व अस्पताल पहुंचाने में रिजॉर्ट प्रबंधन ने मदद नहीं की। यहां एम्बुलेंस भी नहीं मिली। खुद की कार से ले जाना पड़ा। राहुल को स्विमिंग कॉस्ट्यूम में ही अस्पताल लाए थे। कुछ देर बार रिजॉर्ट मैनेजमेंट के कर्मचारी यहां आकर कपड़े वापस ले गए। रिजॉर्ट के मैनेजर नीतेश चतुवेर्दी का कहना है, हमने तुरंत मदद की। व्हीलचेयर लेकर कर्मचारी खुद गए। उसे गाड़ी तक पहुंचाया। एम्बुलेंस मिलती नहीं, इसलिए उनकी ही गाड़ी से अस्पताल के लिए रवाना किया। पीछे से मैं खुद बाइक से पहुंचा था। सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि हमने मदद की या नहीं।

डॉक्टर ने कहा- हार्टअटैक की आशंका डॉ. सुधांशु सेन का कहना है कि राहुल के फेफड़ों में पानी भरा है। बायीं ओर आंख के ऊपर मस्तक पर चोट है, जिससे ब्लीडिंग हुई है। एसडीओपी संजू चौहान ने बताया कि राहुल के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। हार्टअटैक की भी आशंका है। पीएम रिपोर्ट, डेटम टेस्ट में कारण स्पष्ट हो जाएगा।

मढ़ई में बिना अनुमति बना है रिसॉर्ट सतपुड़ा टाइगर रिजर्व (एसटीआर) के कोर एरिया से सारंगपुर (मढ़ई) करीब है। यह ईको सेंसिटिव जोन में आता है। एसटीआर के कोर एरिया के एक से डेढ़ किमी के दायरे में ईको सेंसिटिव जोन माना जाता है। मढ़ई में कुछ रिसॉर्ट ईको सेंसिटिव जोन एरिया में बने है, जो गलत है। ड्रीम व्यू रिसॉर्ट को भी एसटीआर की ओर से लेटर जारी किए हैं। लेकिन, रिसॉर्ट मालिक ने कोर्ट में केस लगाया हुआ है, जो विचाराधीन है। रिसॉर्ट मालिक नीरज सिंह चौहान का कहना है कि हमने सभी अनुमति लेकर ही रिसॉर्ट को बनाया है।

हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने तीन तलाक के मामले में की टिप्पणी

तीन तलाक प्रथा असंवैधानिक और समाज के लिए हानिकारक

इंदौर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने 3 तलाक से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि 3 तलाक असंवैधानिक और समाज के लिए बुरा है। कानून निर्माताओं को यह समझने में कई साल लग गए। अब समय आ गया है कि देश समान नागरिक संहिता की आवश्यकता को समझे। समाज में आज भी आस्था और विश्वास के नाम पर कई कट्टरपंथी, अंधविश्वासी और अति-रूढ़िवादी प्रथाएं प्रचलित हैं। भारत के संविधान में पहले ही से अनुच्छेद-44 शामिल है, जो समान नागरिक संहिता की वकालत करता है, किंतु अब इसे केवल कागज पर नहीं बल्कि वास्तविक बनाया जाए। अच्छी तरह से तैयार समान नागरिक संहिता ऐसे अंधविश्वासों और बुरी प्रथाओं पर रोक लगाने का काम करेगी। इससे राष्ट्र की अखंडता को मजबूती मिलेगी।

बड़वानी जिले के तलाक मामले में थी सुनवाई सोमवार को न्यायमूर्ति अनिल वर्मा ने मप्र के बड़वानी जिले के राजपुर कस्बे की मुस्लिम महिला के तीन तलाक के मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। महिला ने मुंबई निवासी पति, सास और ननद के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई थी। महिला के पति ने उसे 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया था।

महिला को झेलना पड़ता है अत्याचार न्यायमूर्ति वर्मा ने 10 पेज के फैसले में 3 तलाक को गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि इसमें शादी को कुछ ही सेकंड में तोड़ा जा सकता है और वह समय वापस नहीं लाया जा सकता। दुर्भाग्य से यह अधिकार केवल पति के पास है।

शादी के अगले दिन दूल्हे को ब्रेन-हैमरेज, मौत

इंदौर में परिजन बोले- कोई बीमारी नहीं थी, कभी मेडिकल चेकअप भी नहीं कराया

इंदौर। इंदौर में शादी के अगले ही दिन दूल्हे को ब्रेन हेमरेज हुआ। परिवार मैरिज गार्डन से घर लौटने और दुल्हन के मंगल प्रवेश की तैयारी कर रहा था, इसी बीच दूल्हा बाथरूम में गश खाकर गिर गया। अस्पताल में दो दिन इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। घटना राजेंद्र नगर निवासी रिटायर्ड बैंक अधिकारी वर्षा तारे के परिवार में हुई। वर्षा के पति का कई साल पहले निधन हो चुका है। बड़ी बेटी मेघना और बेटा वरुण (38) हैं। वरुण मुंबई की एक कंपनी में जॉब करते थे। 13 जुलाई को शादी थी। इसके पहले गीत-संगीत और 12 जुलाई को रिसेप्शन था। डॉक्टरों के मुताबिक, वरुण को एरेक्नॉइड ब्रेन हेमरेज हुआ था। अस्पताल पहुंचते ही उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। बेहोश होने की स्थिति में एंजियोग्राफी सहित अन्य जांचें कराने की स्थिति नहीं थी। बीपी शूट अप से ब्रेन हेमरेज, ब्लड क्लॉट हुआ डॉक्टर ने कहा- वरुण का बीपी शूट अप हो गया था। इससे उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ और वे गिर गए। सीटी स्कैन में ब्लड का क्लॉट पाया गया। पूरे समय बेहोश होने की वजह से सर्जरी नहीं की जा सकती थी। मौत के पहले भी उनका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा था और तेज बुखार था। दोस्त ने बताया- वरुण वॉश रूम में गिर पड़े शादी के अगले दिन 14 जुलाई को वरुण के परिजन मैरिज गार्डन से घर लौटने के लिए पैकिंग कर रहे थे। इसी बीच वरुण के एक दोस्त ने बताया कि वह वॉश रूम में गिर गए हैं। परिजन पहुंचे तो वे बेसुध थे। तुरंत उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। सीटी स्कैन में पता चला कि ब्रेन हेमरेज हुआ है। न्यूरो सर्जन को बुलाकर दिखाया गया। 15 जुलाई को शाम को सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल रेफर किया गया। यहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। बताया कि हालत में 10त्न ही सुधार है। 16 जुलाई को फिर हालत बिगड़ी और दोपहर 1.30 बजे मौत हो गई। ब्लड प्रेशर या कोई अन्य बीमारी नहीं थी

परिवार का कहना है कि वरुण को ब्लड प्रेशर या कोई अन्य बीमारी नहीं थी। कभी मेडिकल चेकअप भी नहीं कराया था। हालांकि, उनके परिवार की एन्जुरिज्म (नस में गुब्बारा) की हिस्ट्री रही है। यह एक बीमारी है, जिसके लिए एंजियोग्राफी करानी होती है।

पीएमश्री पर्यटन वायु सेवा के लिए कंपनी ने बनाया नया रूट प्लान

भोपाल-ग्वालियर और जबलपुर में रिस्पांस 50% से भी कम, उज्जैन में तकनीकी कारणों से सेवा रोकी

14 जून से 14 जुलाई के बीच आठ शहरों में रही 70 फीसदी आक्यूपेंसी

भोपाल। मध्य प्रदेश में रीजनल कनेक्टिविटी और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीएमश्री पर्यटन वायु सेवा की शुरूआत की है। इसको 14 जुलाई को एक माह पूरा हो गया। आठ शहरों के लिए शुरू की गई पर्यटन सेवा में कुछ रूट पर निजी कंपनी फ्लाय ओला को बहुत कम यात्री मिले हैं। ऐसे में अब कंपनी ने अपने वायु सेवा के रूट का संशोधित प्लान तैयार किया है। जिसके अनुसार सेवा शुरू भी कर दी गई है।

पिछले एक माह में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सिंगरौली, रीवा, उज्जैन एवं खजुराहो के बीच छह सीटर विमान सी-90 विमान से सेवा का संचालन किया है। इसमें भोपाल से ग्वालियर, भोपाल से जबलपुर, इंदौर से जबलपुर और उज्जैन से जबलपुर में कंपनी को 50 प्रतिशत यात्री भी नहीं मिले। 14 जून से 14 जुलाई के आंकड़े के अनुसार 700 यात्रियों की क्षमता पर 550 यात्रियों ने ही यात्रा की। यानी आठ शहरों में कुल 70 प्रतिशत आक्यूपेंसी रही। उज्जैन के लिए वायु सेवा को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि उज्जैन की हवाई पट्टी पर कुछ काम के साथ ही उसकी फैंसिंग का काम होना है। इसके चलते पर्यटन वायु सेवा को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है।

यह बनाया प्लान निजी कंपनी ने अपने एक माह के रिस्पांस के बाद अब अपने रूट में बदलाव कर वायु सेवा का संचालन शुरू किया है। सोमवार को छोड़कर सप्ताह में सभी दिन वायु सेवा का संचालन निजी कंपनी की तरफ से किया जा रहा है। रविवार को भोपाल-इंदौर-ग्वालियर, मंगलवार को भोपाल-जबलपुर-भोपाल-खजुराहो। बुधवार को भोपाल-सिंगरौली-जबलपुर-भोपाल-इंदौर, गुरुवार को भोपाल-इंदौर-खजुराहो-इंदौर-भोपाल, शुक्रवार को भोपाल-ग्वालियर-भोपाल-रीवा-जबलपुर-भोपाल और शनिवार को भोपाल-इंदौर-जबलपुर-इंदौर-भोपाल।

पहले भी बंद हो चुकी है एयर टैक्सी भोपाल में एयर टैक्सी सेवा सफल नहीं रही है। इससे पहले वेंचुरा एयर लाइंस ने एयरटैक्सी सेवा की शुरूआत की थी, लेकिन करीब एक साल में ही उसने सेवा को बंद कर दिया।

सेवा में और विमान जोड़ेंगे वहीं, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के कंपनी सेक्रेटरी अंकित कौरव ने बताया कि उज्जैन में तकनीकी कारणों से रोका है। जल्द ही उसे दोबारा शुरू किया जाएगा। जहां तक कुछ रूट पर यात्रियों की संख्या कम मिलने का सवाल है तो उसके लिए दिन और समय के हिसाब से सेवा देने की योजना पर काम किया जा रहा है। आगे रिस्पांस को देखते हुए सेवा में और भी विमानों को जोड़ा जाएगा।

एक माह में ऐसा रहा रिस्पांस 75 प्रतिशत से अधिक ऑक्यूपेंसी- भोपाल-इंदौर, भोपाल-उज्जैन, इंदौर-उज्जैन, जबलपुर-उज्जैन, रीवा-जबलपुर, रीवा-सिंगरौली, सिंगरौली-रीवा, उज्जैन-इंदौर में कंपनी को 75 प्रतिशत से कम ऑक्यूपेंसी मिली।

50 से 75 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी भोपाल-जबलपुर, भोपाल-खजुराहो, इंदौर-भोपाल, जबलपुर-भोपाल, जबलपुर-खजराहो, जबलपुर-रीवा, खजराहो-भोपाल, उज्जैन-भोपाल में 50 से 75 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी रही।

50 प्रतिशत से कम ऑक्यूपेंसी- भोपाल-ग्वालियर, ग्वालियर-भोपाल, इंदौर-जबलपुर, और उज्जैन-जबलपुर में 50 प्रतिशत से कम ऑक्यूपेंसी रही।

मंत्री रावत की फिर फिसली जुबान, खुद को गृह मंत्री बताया

सिंघार बोले- कहीं आप का लक्ष्य सीएम तो नहीं, कहीं कुछ तो गड़बड़ लग रही है

भोपाल। कांग्रेस से भाजपा में आए राम निवास रावत एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। पहले मंत्री पद की दो बार शपथ लेकर चर्चा में आए थे अब खुद को गृह मंत्री बता दिया। दरअसल रामनिवास रावत को वन और पर्यावरण मंत्रालय सौंपा गया है। रावत की जुबान एक फिर फिसल गई है। जिसके चलते विपक्ष ने उन्हें घेर लिया। रावत ने अपने आप को गृहमंत्री बताते हुए वनों का संरक्षण करने की बात कही है। जिसका एक वीडि यो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कांग्रेस ने उनके इस वीडियों को लेकर कहा है कि आखिर से किस विभाग के मंत्री है। रामनिवास रावत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में वे कह रहे है कि वे गृहमंत्री के रूप में वनों का संरक्षण करेंगे। यह वीडियो सामने आने के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कटाक्ष किया है। सिंघार ने एक्स पर लिखा है कि ये क्या कह और कर रहे हैं रामनिवास जी !!! शपथ ग्रहण के समय आपने मंत्री की जगह राज्यमंत्री पद की शपथ ले ली! अब आपको वन और पर्यावरण मंत्री का दायित्व सौंपा गया तो खुद को गृह मंत्री बता रहे हैं! कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ लग रही है! ऐसा तो नहीं कि आपका लक्ष्य मुख्यमंत्री बनने का हो! आखिर ऐसा कैसे है कि जब भी आप मुंह खोलते हैं, कुछ गलत ही निकलता है! कांग्रेस में तो आप ऐसे नहीं थे। बीजेपी में जाते ही आपकी मनःस्थिति पर इतना गहरा असर कैसे हो गया! मोदी के प्रति आपके अमृत वचन के समय भी आपकी भाव भंगिमाएं उतने समर्पण भाव वाली तो दिखाई नहीं दे रही! अभी तो आपको विपरीत परिस्थितियों में उपचुनाव भी लड़ना है। जरा ध्यान रखिए, मुंह से फिर कुछ गड़बड़ न निकल जाए!

लगता है बहुत जल्दी में है रावत रावत के वीडियो को लेकर कांग्रेस नेता केके मिश्रा ने एक्स पर लिखा है कि ह्यअपनी मातृ संस्था कांग्रेस को अलविदा कर मात्र 15 मिनिट में दो मर्तबा राज्यमंत्री फिर कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने वाले मंत्री रामनिवास रावत जी,जिन्हें शपथ ग्रहण के 13 दिन बाद उट मोहन यादव जी ने वन-पर्यावरण विभाग का जिम्मा सौंपा है (हालाँकि वे बहुत भले व्यक्ति हैं),लगता है बहुत जल्दी में है। ढट नरेंद्र मोदी जी और उट साहब के विकसित-समृद्ध भारत के निर्माण में ह्लदेश के,राज्य के गृह मंत्रीह्व के रूप में उन्हें सहयोग करने का वचन दे रहे हैं ! भाजपा में प्रवेश जरूर ले लिया है किंतु वहां िं423 होने में समय तो लगेगा

भोपाल समेत कई जिलों मे हुई झमाझम, प्रदेश में स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव

30 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट

भोपाल। मध्य प्रदेश में मौसम का स्ट्रॉन्ग सिस्टम तेज बारिश करा रहा है। सोमवार को राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में बारिश हुई। सिवनी में 4 इंच से ज्यादा पानी गिर गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में 30 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में अभी तक हुई बारिश को लेकर मौसम विभाग ने सोमवार को आंकड़े जारी किए हैं, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश में 1 जून से 22 जुलाई 2024 तक औसत से 6 प्रतिशत कम बारिश हुई है। पूर्वी मध्य प्रदेश में औसत से 17 प्रतिशत कम बारिश हुई है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में औसत से 5 प्रतिशत अधिक पानी गिरा है। पूर्वी क्षेत्र में अभी भी कई जगह बहुत कम बारिश हुई है जिससे किसानों की परेशानी बड़ी हुई है।

प्रदेश के इन क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ बिजली का गिरने का अलर्ट मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे को लेकर मौसम विभाग भोपाल ने अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि सिवनी, बालाघाट में बिजली के साथ बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।साथ ही रायसेन सांची, दक्षिण विदिशा, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना पेंच, उमरिया बांधवगढ़, डिंडोरी में बिजली के साथ भारी बारिश के साथ मध्यम गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। आगर, राजगढ़, पूर्वी नर्मदापुरम पचमढ़ी, सागर, मंदसौर गांधीसागर बांध, दमोह, छतरपुर, मंडला कान्हा, शहडोल, अनुपपुर अमरकंटक, कटनी में बिजली गिराने की संभावना है। दक्षिण गुना, दक्षिण श्योपुरकलां, देवास में बिजली के साथ हल्की आंधी इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, खंडवा, हरदा, सीहोर, पश्चिम नर्मदापुरम, बैतूल, उत्तर विदिशा उदयगिरि, भीमबेटका, नीमच, टीकमगढ़, खजुराहो, पन्ना टीआर, मैहर, सतना, जबलपुर भेड़ाघाट एपी, सीधी, रात में सिंगरौली, रीवा, भोपाल बैरागढ़, निवाड़ी ओरछा, रतलाम धोलावाड़, उत्तरी झाबुआ, उत्तरी धार, देवास में भी बारिश का अनुमान है।

` प्रदेश में कहां कितना हुई बारिश सोमवार को प्रदेश में रतलाम, बैतूल, नर्मदापुरम, रतलाम, उज्जैन, दमोह, जबलपुर, खजुराहो, सागर में भी हल्की बारिश हुई। सिवनी में सुबह 8.30 से शाम 5.30 बजे के बीच 9 घंटे में 106 मिमी यानी, 4 इंच से ज्यादा पानी गिर गया। पचमढ़ी में करीब एक इंच बारिश हुई। भोपाल, मंडला और बालाघाट जिले के मलाजखंड में पौन इंच पानी गिरा। छिंदवाड़ा में बारिश के बाद मकानों में पानी भरा गया। इधर मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में नर्मदापुरम और देवास में भारी बारिश का भी अनुमान जताया है। इसके अलावा सीहोर, रायसेन के भीमबेटका, दक्षिण विदिशा, हरदा, दक्षिण सिवनी, दक्षिण बालाघाट में आकाशीय बिजली चमकने के साथ मध्यम गरज के साथ बारिश की संभावना है।झ

भोपाल में तीन दिनी आत्मनिर्भर पंचायत कांफ्रेंस आज से

भोपाल।'आत्मनिर्भर पंचायत, समृद्ध मध्य प्रदेश' के विषय को लेकर 23 से 25 जुलाई तक कुशाभाऊ ठाकरे कंवेंशन हॉल भोपाल में तीन दिवसीय कांफ्रेंस होगी। इसकी जानकारी पंचायत ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि पहली बार जिला पंचायत तथा जनपद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सीईओ उद्घाटन सत्र से ही उपस्थित रहेंगे। कांफ्रेंस का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे। इसके उदघाटन सत्र में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विजय शाह, संपतियां उइके, एंदल सिंह कंसाना और स्वतंत्र प्रभार मंत्री लखन पटेल उपस्थित होंगे।

पटेल ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में जर्मन संस्था जीआईजेड जिसका भारत सरकार से समन्वय है और पंचायती राज से जुड़े कार्यों को संपादित करती है, वह भी अपने कार्यों को प्रदर्शित करेगी। दूसरे दिन जनपद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पूरे दिन उपस्थित रहेंगे तथा उद्घाटन सत्र में जिन मंत्रियों को आमंत्रित किया गया था, उनके रिपोर्ट्स को सभी के बीच में रखा जाएगा। तीसरे दिन जिला पंचायत सदस्य भी कांफ्रेंस में उपस्थित रहेंगे तथा इस दिन कांफ्रेंस का समापन भी होगा। पटेल ने बताया कि उन्होंने इस कांफ्रेंस को लेकर मुद्दों को चार ग्रुप में बांटा है, जिसमें सबसे पहले शहरी क्षेत्र के आसपास जो ग्राम पंचायतें हैं उनके विकास को लेकर चर्चा होगी, जिसकी अध्यक्षता शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय करेंगे तथा चर्चा के आधार पर कांफ्रेंस के बाद उन समस्याओं के निराकरण को लेकर काम होगा। दूसरे ग्रुप में अध्यक्षता पीएचई मंत्री संपत्तियां उईके करेंगी और इस ग्रुप में केंद्र से प्राप्त होने वाली सहायता तथा मनरेगा जैसी योजनाओं के साथ जुड़ी हुई समस्याओं पर चर्चा होगी।

पिकनिक मनाने गया भोपाल का परिवार अमरगढ़ वाटर फॉल में फंसा

चार घंटे रेस्क्यू के बाद सुरक्षित निकाला

भोपाल। भोपाल का एक परिवार जिले के शाहगंज स्थित अमरगढ़ वाटर फॉल में फंस गया। परिवार के पांच सदस्य रविवार को पिकनिक मनाने यहां पहुंचे थे। रविवार को शाहगंज, बुधनी में तेज बारिश होने के कारण शाम को घर लौटते समय अचानक नदी में पानी बढ़ गया और सभी लोग नदी में बने एक टापू पर फंस गए। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम रेस्क्यू करने मौके पर पहुंची और करीब चार घंटे के अथक प्रयासों को बाद रात दस बजे के करीब सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। शाहगंज से करीब 10 किलोमीटर दूर खटपुरा गांव से जाने का रास्ता अमरगढ़ वॉटरफॉल का है। अमरगढ़ वॉटरफॉल में प्रतिबंध के बावजूद भी चारों और जंगल और हरियाली की मौजूदगी देखने बड़ी संख्या में लोग प्रकृति के बीच पहुंच रहे हैं। बताया जाता है कि भोपाल एयरपोर्ट रोड के पास निवास करने वाले अशोक माहेश्वरी अपने माता-पिता, पत्नी और भाई के साथ रविवार को अमरगढ़ झरने पर पहुंचे थे। जहां पर ये लोग फंसे थे, वहां पर टापू था। दोनों तरफ पानी था। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया गया और करीब चार घंटे के अथक प्रयासों के बाद सभी को रात करीब दस बजे बाहर निकाला। बताया जाता है कि परिवार को निकालने के लिए दोनों ओर ट्रैक्टर से रस्सी बांधी गई फिर रस्सी के सहारे सभी को बाहर निकाला गया। शाहगंज थाना प्रभारी पंकज बास्कले ने बताया कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। रेस्क्यू करने में करीब चार घंटे का समय लगा।

हमीदिया अस्पताल पहुंच सीएम ने जाने मरीजों के हाल

अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर की कई घोषणाएं

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव सोमवार को अचानक हमीदिया अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे इस दौरान उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत की इस दौरान उन्होंने कहा कि हमीदिया परिसर में एक और बिल्डिंग बनेगी। जो भी नई डिमांड है, सब पूरी होगी। कम इस दौरान बच्चा वार्ड में पहुंचे और छोटे बच्चों को दुलार भी किया। सीएम ने अस्पताल अधीक्षक डॉ. सुनीत टंडन से अस्पताल में बनी अलग-अलग बिल्डिंग के संचालित विभिन्न डिपार्टमेंट्स केबारे में जानकारी ली। साथ ही हॉस्पिटल के इमरजेंसी एग्जिट और एंट्री को लेकर भी डॉक्टरों से चर्चा की। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीदिया, प्रदेश का सबसे बड़ा शासकीय अस्पताल है। इस हॉस्पिटल में 2250 बेट तक की क्षमता है। 1800 तक बेड तैयार हैं। यह मरीजों को आने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

बारिश में मरीजों को आने में ना हो कोई परेशानी मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि वर्षा काल चल रहा है, वर्षा काल में हमारे जो रेगुलर मरीज आ रहे हैं, वो स्वाभाविक रूप से आयेंगे, लेकिन मरीजों को आने में कोई कठिनाई न हो डॉ यादव ने कहा कि हमीदिया हॉस्पिटल प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जिसकी अपनी क्षमता 2250 बेड की है। अभी करीब 1850 बेड तैयार है। इनमें करीब 1400 मरीज हैं। हमारा हॉस्पिटल का मैनेजमेंट चल रहा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें किसी को कठिनाई नहीं आए। कुछ नए काम की दृष्टि से यहां मेरे पास प्रस्ताव भी आए हैं।

सीएम ने कर दी ये बड़ी घोषणाएं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी 35 करोड़, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और आर्थोपेडिक्स 42 करोड़ और कैंसर उपचार के लिए नई मशीनें 30 करोड़ रुपये के प्रस्ताव आए हैं। बोर्नमेरो सेंटर जल्दी प्रारंभ किया जाएगा। पीजी छात्रों के लिए नया छात्रावास ब्लॉक 20 करोड़ का, एमआरआई सिटी मशीन जल्द ही 20 करोड़ की आने वाली है। नया एकीकृत ओपीडी ब्लॉक 35 करोड़ का ये हाईराइस बिल्डिंग बनेगी, नया यूजी छात्रावास 17 करोड़ का बनेगा।

हेल्थ के मामले में हमारी सरकार बहुत गंभीर विकास के मामले में, हेल्थ के मामले में हमारी सरकार बहुत गंभीर है। सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले राशि का उपयोग प्रॉपर हो इससे जनता के बीच में एक विश्वास बनता है। और सरकारी अस्पतालों में जनता का विश्वास भी है। हमारा प्रयास है कि इन सभी कामों में गुणवत्ता और दक्षता के साथ सभी अपनी ड्यूटी करें। समय-समय पर निरीक्षण करने से स्वाभाविक रूप से एक विश्वास बनता है। हॉस्पिटल एक ऐसा स्थान है, जहां जनता कष्ट में तुरंत दौड़कर आती है। अस्पताल सुविधाओं की दृष्टि से प्रॉपर काम करें।

बेटा होने पर सीएम ने परिजनों को दी बधाई मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव अस्पताल के ब्लॉक-2 बिल्डिंग में स्त्री और प्रसूति रोग विभाग में पहुंचे। यहां वेटिंग एरिया में मरीजों के परिजन से बात की। एक महिला अटेंडर से उन्होंने पूछा, क्या हाल है अटेंडर ने जवाब दिया, बेटा हुआ है। सब ठीक है। इस पर सीएम ने कहा, अरे वाह बधाई आपको सीएम शिशु रोग विभाग में भी जाकर व्यवस्थाएं देखीं। सीएम ने पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे फ्लोर पर कई वार्ड में जाकर मरीजों के साथ उनके परिजनों से बातचीत की। अस्पताल प्रबंधन से इस बात पर भी चर्चा की कि अस्पताल में क्या सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं।

बारिश के मौसम में सड़कों पर गोवंश दिखे तो मालिक पर होगी कार्रवाई

भोपाल। शहर की सड़कों पर वर्षा शुरू होने के बाद से गोवंश की संख्या बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि शहर के पशु चिकित्सालय और आसरा स्थलों पर भी इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में नगर निगम भोपाल ने गोवंश को छोड़ने वाले मालिकों से अपील की है कि वह उपयोग के बाद इस तरह खुला न छोड़ें। साथ ही नगर निगम आयुक्त हरेंद्र नारायन ने निर्देश दिए हैं कि सड़कों पर स्वतंत्र विचरण करने वाले पशुओं को पकड़कर कांजी हाउस, गोशालाओं में भेजने की कार्रवाई करें। इसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न करने वाले पशु पालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नगर निगम आयुक्त ने वर्षा के दौरान शहर में बेसहारा गोवंश की बढ़ती संख्या को देखते हुस समीक्षा की और कहा कि इनकी वजह से आवागमन बाधित होता है और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर गोवंश के कारण दुर्घटनाएं भी हो रही है। जिसमें नागरिकों के घायल होने के साथ ही गोवंश के घायल होने की घटनाओं में भी लगातार वृद्धि हो रही है। भोपाल नगर नि?गम की गौवर्धन परियोजना शाखा द्वारा प्रतिदिन औसतन 30 गोवंश को आसरा और पशु चिकित्सालयों में उपचार के लिए भेजा जा रहा है। जबकि पहले यह संख्या 10 के आसपास थी। तीन गुना होने के बाद भी में सुधार नहीं है। शहर में जगह जगह गोवंश सड़कों पर नजर आता है।

साम्पदकीय

सर्वर के सहारे दुनिया

दुनिया के बड़े आर्थिक तंत्र के घटकों के लिए यह एक खास किस्म की विकलांगता है। दुनिया के 95 फीसदी से अधिक कम्प्यूटर माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम से ही चलते हैं। उनका भरोसा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सिस्टम में कभी गड़बड़ी नहीं होगी, लेकिन सिर्फ एक खामी ने दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी को बेनकाब कर दिया है।

विख्यात कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में क्या साइबर खामी आई कि लगभग दुनिया की सांसें हांफने लगीं। गतिविधियां थम गईं। अमरीका समेत जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया सरीखे विकसित और प्रगतिवादी देशों में उड़ानें अवरुद्ध हो गईं अथवा रद्द करनी पड़ीं। उड़ानों के अलावा, बैंकिंग, रेलवे, स्टॉक एक्सचेंज, अस्पताल, रेस्तरां, डिजिटल पेमेंट्स, टीवी चैनलों से लेकर सुपर मार्केट सरीखी अत्यावश्यक सेवाएं ठहर गईं। कइयों को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। माइक्रोसॉफ्ट का यह एकाधिकार बेहद खतरनाक है। क्या इतने बड़े देशों के ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही कंपनी के सर्वर के भरोसे होने चाहिए? दुनिया के बड़े आर्थिक तंत्र के घटकों के लिए यह एक खास किस्म की विकलांगता है। दुनिया के 95 फीसदी से अधिक कम्प्यूटर माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम से ही चलते हैं। उनका भरोसा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सिस्टम में कभी गड़बड़ी नहीं होगी, लेकिन सिर्फ एक खामी ने दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी को बेनकाब कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट को साइबर सुरक्षा देने वाली कंपनी- क्राउडस्ट्राइक-के अपडेट के कारण यह खामी पैदा हुई या पूरे सिस्टम में ही गड़बड़ी आई, लेकिन पूरी दुनिया सहम-सी गई, असमंजस में पड़ गई कि अब क्या किया जाए? ऐसे सर्वर की विश्वव्यापी सेवाएं देने वाली कंपनी के पास कमोबेश वैकल्पिक योजना होनी चाहिए थी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने किसी प्लान बी का इस्तेमाल नहीं किया। कंपनी सोचती रही कि साइबर सुरक्षा कंपनी क्राउडस्ट्राइक इस खामी को दुरुस्त करेगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यह एक ही सर्वर के भरोसे दुनिया चलाने की खतरनाक स्थिति है। ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट के विकल्प नहीं हैं। कई कंपनियां लाइनेक्स और मेक का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट का एकाधिकार है। चीन और रूस पर इस साइबर संकट का कोई भी असर नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने यह आशंका काफी पहले भांप ली थी, लिहाजा उन्होंने अपने-अपने सिस्टम को विकसित किया। उनके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, सर्वर हैं, वे पश्चिम के भरोसे नहीं हैं। उनके पश्चिम के साथ संबंध भी बेहतर नहीं हैं। भारत को इस वैश्विक संकट से सबक सीखना चाहिए। हालांकि पहले दिन शुक्रवार, 19 जुलाई को दुनिया भर में 4295 हवाई उड़ानें रद्द करनी पड़ीं, लेकिन भारत में भी 200 उड़ानें रद्द की गईं। भारत की अधिकतर साइबर प्रणालियां माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से ही जुड़ी हैं। जरा कल्पना करें कि सर्वर फेल हो जाए और हमारा ऊर्जा-उत्पादन, थर्मल प्लांट, उड़ानें, मेट्रो समेत रेलवे सिस्टम, बैंकिंग और एटीएम, संचार, अस्पताल, डिजिटल लेन-देन आदि बुनियादी और अत्यावश्यक सेवाएं रुक जाएं, तो भारत ही ठप हो जाएगा! सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट और यूपीआई जैसे वित्तीय प्रौद्योगिकी सिस्टम बनाना हमारी क्षमताओं को बयां करते हैं। भारत चांद तक अपने अभियान की सफल यात्रा कर चुका है। हम आदित्य एल-1 अभियान के जरिए सूर्य का व्यापक अध्ययन कर रहे हैं। अंतरिक्ष में अनेक उपग्रह भेज चुके हैं। सॉफ्टवेयर के सर्वाधिक कुशल चेहरे हिंदुस्तान पैदा कर रहा है, जिनकी दुनिया भर में खूब मांग है। तो हम भारत का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर, पूरी तरह लागू क्यों नहीं कर सकते। इतनी संवेदनशील सेवाओं के लिए हम पराश्रित क्यों हैं? अब कुछ सवाल हैं, जो आने वाले वक्त में स्पष्ट होंगे। मसलन-माइक्रोसॉफ्ट की ग्राहक कंपनियां अपने घाटे की भरपाई कैसे करती हैं? क्या मूल कंपनी उन्हें मुआवजा देगी? क्या इस तरह का कोई अनुबंध है? यदि माइक्रोसॉफ्ट किसी भी किस्म का मुआवजा नहीं देती है, तो क्या उसे अदालत में घसीटा जा सकता है? क्या ग्राहक कंपनियों के पास ऐसे अधिकार हैं? दरअसल हम इसे माइक्रोसॉफ्ट की बुनियादी खामी मानते हैं, क्योंकि बाजार में उसी की प्राथमिक ख्याति है। क्राउडस्ट्राइक से कंपनियों ने करार नहीं किया था। अलबत्ता वह माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ी कंपनी जरूर है। सवाल यह भी हो सकता है कि क्राउडस्ट्राइक जो अपडेट कर रही थी, उसे जांचने का काम सिर्फ उसका था अथवा माइक्रोसॉफ्ट का भी था?

खाद्य सुरक्षा और स्थिरता में भी देश को बनाना है वैश्विक गुरु

स्वास्थ्य मंत्रालय और एफएसएसएआई हमारे देश के खाद्य सुरक्षा परिदृश्य को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। एक मजबूत खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत खाद्य-नीतियों और मानकों की नींव पर ही गढ़ा जा सकता है। ऐसे में, यह जानकर खुशी हुई है कि एफएसएसएआई के वैज्ञानिक पैनल व विशेषज्ञ समितियों का काफी विस्तार हुआ है। इनमें 88 संगठनों के 286 विशेषज्ञ शामिल हैं। इससे वैश्विक मानकों के अनुरूप मानदंडों और नीतियों के विकास की गति में उल्लेखनीय तेजी आई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय और एफएसएसएआई हमारे देश के खाद्य सुरक्षा परिदृश्य को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। एक मजबूत खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत खाद्य-नीतियों और मानकों की नींव पर ही गढ़ा जा सकता है। ऐसे में, यह जानकर खुशी हुई है कि एफएसएसएआई के वैज्ञानिक पैनल व विशेषज्ञ समितियों का काफी विस्तार हुआ है। इनमें 88 संगठनों के 286 विशेषज्ञ शामिल हैं। इससे वैश्विक मानकों के अनुरूप मानदंडों और नीतियों के विकास की गति में उल्लेखनीय तेजी आई है।

एफएसएसएआई की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलेट के मानकों का सृजन है, जिनको साल 2023 में वैश्विक मिलेट (श्री अन्न) सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। ये मानक कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग के साथ साझा किए गए हैं। इससे मिलेट के वैश्विक मानकों के विकास और भारत को एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने के लिए नीतियों व मानकों के विकास के साथ-साथ उनका प्रवर्तन और परीक्षण भी आवश्यक है। एफएसएसएआई के खाद्य-परीक्षण के बुनियादी ढांचे में बीते आठ वर्षों में काफी सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में कैबिनेट ने राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को मजबूत करने के लिए 482 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। एफएसएसएआई ने फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स नाम से मोबाइल फूड लैब उपलब्ध कराकर दूरदराज के इलाकों में पहुंचना शुरू कर दिया है। इन उपलब्धियों का उत्सव मनाते समय, हमें वैश्विक स्तर पर उभर रहे रुझानों, जैसे कि वनस्पति आधारित प्रोटीन, प्रयोगशाला में विकसित मांस आदि को भी स्वीकार करना चाहिए। एफएसएसएआई ने नई श्रेणियों- जैसे वीगन खाद्य पदार्थों, जैविक उत्पादों व आयुर्वेदिक आहार के लिए सक्रिय रूप से मानक विकसित किए हैं और यह खाद्य-सुरक्षा के उभरते रुझानों के अनुरूप निरंतर अनुकूलन कर रहा है।

जैसे-जैसे वैश्विक खाद्य व्यापार का विस्तार हो रहा है, एफएसएसएआई कोडेक्स जैसे विभिन्न मंचों पर अंतरराष्ट्रीय नियामकों के साथ साझेदारी कर रहा है। इसका उद्देश्य बढ़ती आबादी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को साझा करना और सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करना है। एफएसएसएआई ने साल 2023 में दिल्ली में पहला वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन (जीएफआरएस) भी आयोजित किया, जो खाद्य नियामकों के लिए उभरती खाद्य सुरक्षा चुनौतियों के बारे में मिलने और विचार-विमर्श करने के लिए अपनी तरह का पहला सहयोगी मंच है।

जब हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं, तो नागरिकों और उपभोक्ताओं को हमें साक्ष्य-आधारित जानकारी के माध्यम से विभिन्न खाद्य सुरक्षा मुद्दों पर सशक्त भी बनाना होगा। तभी हमारा काम समग्रता से पूर्ण होगा। यहीं पर एफएसएसएआई का ईट राइट इंडिया अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह सुनिश्चित करके कि उपभोक्ताओं तक हर स्तर पर जरूरी जानकारी पहुंचे। इस परिवर्तनकारी कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है, ताकि हमारी पहुंच बढ़ेऔर व्यावहारिक बदलाव को प्रोत्साहित किया जा सके। यह उपभोक्ताओं को सुरक्षित व स्वास्थ्यप्रद खाद्य विकल्पों की मांग करने के लिए सशक्त बनाता है और खाद्य व्यवसाय को बेहतर विकल्प प्रदान करने के लिए प्रेरित करता है। एफएसएसएआई, 2006 खाद्य-उत्पादों के लिए व्यापक मानकों को अनिवार्य बनाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे उपभोग के लिए सुरक्षित हैं। साथ ही, फूड लेबलिंग के नियम उपभोक्ता को एक सूचित विकल्प (इंफोर्मड च्वाइस) चुनने में सशक्त करते हैं। विज्ञापन और दावों की नीतियां यह सुनिश्चित करती हैं कि खाद्य व्यवसायों द्वारा उत्पादों के बारे में कोई भ्रामक दावा नहीं किया जा रहा है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज करने का पर्याप्त तंत्र प्रदान करके उनके सामने आने वाली आधुनिक चुनौतियों के समाधान में सहायक रहा है, विशेष रूप से भ्रामक विज्ञापनों और असुरक्षित या घटिया भोजन से संबंधित शिकायतों के संदर्भ में।

खाद्य सुरक्षा एक सामूहिक प्रयास है, और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण विभिन्न सरकारी विभागों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है। यह संपूर्ण सरकार (होल-ऑफ-गवर्नमेंट) और संपूर्ण प्रणाली (होल-ऑफ-सिस्टम) दृष्टिकोण को अपना रहा है। एफएसएसएआई खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलों में उद्योगों और अन्य हितधारकों को शामिल करके एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने पिछले दस वर्षों में भारत की खाद्य सुरक्षा स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से बदला है। इसके साथ ही, यह उभरती चुनौतियों का समाधान करने और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। एफएसएसएआई का लक्ष्य अपनी प्रतिबद्धता और समग्र दृष्टिकोण से भारत को खाद्य-उत्पादन में ही नहीं, बल्कि खाद्य सुरक्षा और स्थिरता में भी वैश्विक गुरु बनाना है।

नए बजट से मध्यम वर्ग की उम्मीदें

ऐसे में देश में आयकर संग्रहण सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आकार की तुलना में महज 11.7 फीसदी ही है, जबकि यह जर्मनी में 38 फीसदी, जापान में 31 फीसदी, ब्रिटेन में 25 फीसदी, अमेरिका में 25 फीसदी और चीन में 18 फीसदी है। स्थिति यह है कि अमेरिका की 60 फीसदी और ब्रिटेन की 55 फीसदी आबादी आयकर चुकाती है। दुनिया की कई छोटी-छोटी अर्थव्यवस्थाओं में संग्रहित किए जाने वाले आयकर का उनकी जीडीपी में बड़ा योगदान है। अतएव हम उम्मीद करें कि इस बार वित्तमंत्री नए बजट से ऐसे लोगों को चिन्हित करने की नई रणनीति के साथ दिखाई देंगी, जिससे वास्तविक आमदनी का सही मूल्यांकन हो सके, लोगों के वित्तीय लेन-देन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही जो वास्तविक कमाई से कम पर आयकर देते हैं, उन्हें भी चिन्हित किया जा सके। इस समय पूरे देश की निगाहें 23 जुलाई को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट 2024-25 की ओर लगी हुई हैं। यह उम्मीद की जा रही है कि वर्ष 2012-13 के बाद महंगाई के हिसाब से जिस आयकरदाता और मध्यम वर्ग को राहत नहीं मिली है, अब वित्तमंत्री नए बजट के माध्यम से आयकरदाता और मध्यम वर्ग की क्रयशक्ति बढ़ाकर मांग में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था को गतिशील करने की रणनीति पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकती हैं। इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि मध्यम वर्ग को राहत देने को लेकर विशेष रूप से कोरोना महामारी के बाद लगातार मांग तेज हुई है। सरकार ने विगत वर्षों में जहां गरीब लोगों के लिए ढेर सारी राहतों का ऐलान किया, वहीं कॉरपोरेट जगत पर भी सरकार ने ध्यान दिया। लेकिन राहत पाने के मद्देनजर सबसे अधिक टैक्स देने वाला मध्यम वर्ग पीछे छूट गया। 18वीं लोकसभा चुनाव के मतदान में मध्यम वर्ग की नाराजगी भी दिखाई दी है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक संबोधन में कहा है कि मध्यम वर्ग देश के विकास का चालक है और मध्यम वर्ग कैसे कुछ बचत बढ़ा सके तथा मध्यम वर्ग के लोगों की जिंदगी को कैसे आसान बनाया जा सके, इस परिप्रेक्ष्य में रणनीतिकपूर्वक आगे बढ़ा जाएगा। गौरतलब है कि इस पूर्ण बजट 2024-25 के

समय वित्तमंत्री सीतारमण के पास आयकर संबंधी मजबूत परिदृश्य मौजूद है। पिछले 10 वर्षों में आयकर रिटर्न भरने वाले आयकरदाताओं की संख्या और आयकर की प्राप्ति में छलांगे लगाकर वृद्धि हुई है। 2023-24 में आयकर रिटर्न रिकॉर्ड 8 करोड़ के स्तर को पार कर चुका है और पिछले 10 वर्षों में आयकर रिटर्न भरने वाले दोगुने से अधिक हुए हैं। आयकर विभाग के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2013-14 में आयकर संग्रह करीब 2.38 लाख करोड़ रुपए था। यह फिर तेजी से बढ़ता गया। यह वर्ष 2019-20 में 10.5 लाख करोड़ रुपए हो गया। कोरोनाकाल के कारण यह वर्ष 2020-21 में घटकर 9.47 लाख करोड़ रुपए पर आ गया। यह वर्ष 2021-22 में 14.08 लाख करोड़ रुपए, वर्ष 2022-23 में 16.64 लाख करोड़ रुपए और वर्ष 2023-24 में 19.58 लाख करोड़ रुपए हो गया। ऐसे में वित्तमंत्री सीतारमण मजबूत वित्तीय मुट्ठी से आयकर के नए और पुराने दोनों स्लैब की व्यवस्थाओं के तहत करदाताओं व मध्यम वर्ग को अभूतपूर्व राहतों से लाभान्वित कर सकती हैं। खासतौर से वेतनभोगी वर्ग को लाभान्वित करने के भी विशेष प्रावधान नए बजट में दिखाई दे सकते हैं। इसके तहत मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) सीमा को 50000 रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए तक किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2018 में मानक कटौती की सीमा 40 हजार रुपए थी और वर्ष 2019 में इसे बढ़ाकर 50 हजार रुपए किया गया था। नए बजट के तहत आयकर से संबंधित विभिन्न टैक्स छूटों में वृद्धि की जा सकती है। मौजूदा समय में धारा 80 सी के तहत 1.50 लाख रुपए की छूट मिलती है। इसके तहत ईपीएफ, पीपीएफ, एनएससी, जीवन बीमा, बच्चों की ट्यूशन फीस और होम लोन का मूलधन भुगतान भी शामिल है। मकानों की बढ़ती हुई कीमत को देखते हुए धारा 80 सी के तहत 2.5 लाख से तीन लाख की छूट दी जा सकती है। इसी तरह सरकार के द्वारा इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 डी के तहत कर कटौती की सीमा को बढ़ा सकती है। ऐसे में सरकार के द्वारा 80 डी के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट को बढ़ा सकती है ताकि टैक्पेयर्स हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर प्रेरित हों। 80 डी में कर छूट सीमा को बढ़ाने के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सीमा बढ़ाई जाने से लोगों को स्वास्थ्य बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) में योगदान की वार्षिक सीमा को मौजूदा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जा सकता है। निस्संदेह देश में कर सुधारों से आयकर के संग्रहण में आशातीत वृद्धि हुई है। लेकिन अभी आयकर के कर दायरे में इजाफा किए जाने की बड़ी संभावनाएं हैं। जहां वर्ष 2024-25 के बजट से वित्तमंत्री आयकर राहत संबंधी उपहार सौंप सकती हैं, वहीं वे बजट में आयकर के दायरे का विस्तार करने की नई रणनीति का ऐलान कर सकती हैं। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि बड़ी संख्या में उद्योग-कारोबार सेक्टर में कार्यरत रहते हुए कमाई करने वाले, महंगी आरामदायक व विलासिता की वस्तुओं का उपयोग करने वाले, पर्यटन के लिए विदेश यात्राएं करने वालों में से बड़ी संख्या में लोग या तो आयकर न देने का प्रयास करते हैं या फिर बहुत कम आयकर देते हैं। विभिन्न रिपोर्टों के मुताबिक पिछले एक वर्ष में करीब 24 लाख लोगों ने 10 लाख रुपए से महंगी कारें खरीदी, पिछले एक वर्ष में करीब 25 लाख लोगों ने 50 लाख रुपए से अधिक कीमत के महंगे घर खरीदे, वर्ष 2022 में देश के करीब 2.16 करोड़ लोगों ने पर्यटन के मद्देनजर विदेश यात्राएं की। इस तरह लोगों के पास पर्याप्त कमाई के कारण ही ये खरीदियां और विदेश यात्राएं संभव हैं। लेकिन ऊंची कमाई करके भी बड़ी संख्या में लोग आयकर नहीं देना चाहते। वर्ष 2023-24 में देश के 140 करोड़ से अधिक लोगों में से सिर्फ 2.79 करोड़ लोगों ने ही आयकर दिया है। यानी देश की आबादी के 1.97 फीसदी लोगों ने ही आयकर दिया है। ऐसे में आयकर का पूरा बोझ दो फीसदी से भी कम आबादी के द्वारा उठाया जा रहा है। साथ ही देश में कुल आयकर रिटर्न के करीब 70 फीसदी आयकर रिटर्न शून्य आयकर देयता बताते हुए दिखाई दिए हैं। ऐसे में देश में आयकर संग्रहण सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आकार की तुलना में महज 11.7 फीसदी ही है, जबकि यह जर्मनी में 38 फीसदी, जापान में 31 फीसदी, ब्रिटेन में 25 फीसदी, अमेरिका में 25 फीसदी और चीन में 18 फीसदी है। स्थिति यह है कि अमेरिका की 60 फीसदी और ब्रिटेन की 55 फीसदी आबादी आयकर चुकाती है। दुनिया की कई छोटी-छोटी अर्थव्यवस्थाओं में संग्रहित किए जाने वाले आयकर का उनकी जीडीपी में बड़ा योगदान है। अतएव हम उम्मीद करें कि इस बार वित्तमंत्री नए बजट से ऐसे लोगों को चिन्हित करने की नई रणनीति के साथ दिखाई देंगी, जिससे वास्तविक आमदनी का सही मूल्यांकन हो सके, लोगों के वित्तीय लेन-देन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही जो वास्तविक कमाई से कम पर आयकर देते हैं, उन्हें भी चिन्हित करके अपेक्षित आयकर चुकाने के लिए बाध्य किया जा सके। निश्चित रूप से इससे देश में टैक्स संग्रहण बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

सावन में भक्तों के लिए जल्दी उठ रहे बाबा महाकाल, चलित भस्मारती में 40 हजार भक्तों ने किए दर्शन

विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज बाबा महाकाल प्रतिदिन की बजाय एक घंटा पहले यानी की भक्तों को दर्शन देने के लिए रात तीन बजे जागे। यहां सबसे पहले वीरभद्र की आज्ञा लेकर चांदी गेट खोले गए और उसके बाद बाबा महाकाल का विशेष पूजन दर्शन और भस्म आरती की गई।श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित आशीष पुजारी ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितिया और मंगलवार के महासंयोग पर मंगलवार सुबह तीन बजे भस्म आरती के दौरान वीरभद्र जी से आज्ञा लेकर मंदिर के पट खुलते ही पण्डे पुजारियों ने गर्भगृह में स्थापित सभी भगवान की प्रतिमाओं का पूजन कर भगवान महाकाल का जलाभिषेक दूध, दही, घी, शक्कर पंचामृत और फलों के रस से किया। इसके बाद प्रथम घंटाल बजाकर हरि ओम का जल अर्पित किया गया। मंगलवार के शृंगार की विशेष बात ये रही कि आज बाबा महाकाल को मावे और ड्रायफ्रूट से सजाने के साथ मखाने और डमरू की माला पहनाई गई थी। बाबा महाकाल को डमरू की माला पहनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि उन्हें डमरू अति प्रिय है। इसीलिए श्रावण मास में उन्हें डमरू की माला अर्पित की गई। पुजारियों ओर पुरोहितों द्वारा इस दौरान बाबा महाकाल का विशेष शृंगार कर कपूर आरती के बाद बाबा महाकाल को नवीन मुकुट व मुंड माला धारण करवाई गई। महानिर्वाणी अखाड़े की और से भगवान महाकाल को भस्म अर्पित की गई। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दिव्य दर्शनों का लाभ लिया। जिससे पूरा मंदिर परिसर जय श्री महाकाल की गूंज से गुंजायमान हो गया। श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रावण माह के पहले दिन श्री महाकालेश्वर मन्दिर प्रबन्ध समिति द्वारा श्रावण-भाद्रपद माह में श्रद्धालुओं की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए भस्मारती के दौरान चलित भस्मारती में निःशुल्क प्रवेश दिया गया। इसमें बिना पंजीयन के लगभग 40 हज़ार भक्तों ने चलित रूप (बिना रुके) से भगवान श्री महाकालेश्वर जी के भस्मारती के दर्शन किए। श्री महाकालेश्वर भगवान के पट खुलते ही श्रद्धालुओं ने निःशुल्क चलित भस्मारती की व्यवस्था में दर्शन किए। ज्ञात हो कि श्रावण- भाद्रपद माह में श्रद्धालुओं की अधिक संख्या को देखते हुए अनुमति नहीं मिलने से श्रद्धालु निराश हो जाते थे।

प्रजा का हाल जानने निकले बाबा महाकाल

एक झलक पाने आतुर दिखे श्रद्धालु, 2.15 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन

उज्जैन, उज्जैन में बाबा महाकाल की पहली शाही सवारी निकल रही है। महाकाल ने श्रद्धालुओं को मनमहेश स्वरूप में दर्शन दिए हैं। मान्यता है कि वर्षा काल में सृष्टि का संचालन करने वाले सभी देवता शयन काल में चले जाते हैं। जबकि बाबा महाकाल सृष्टि का संचालन करते हैं। ऐसे में सावन मास में महाकाल प्रजा का हाल जानने निकलते हैं। आज सावन का पहला सोमवार है, और खास बात यह है कि इस पवित्र माह की शुरुआत भी सोमवार से हुई है। इससे पहले महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी-लंबी कतारें लगी रहीं। मंदिर प्रशासन ने दावा है कि कतार में लगे भक्त को गर्भगृह तक आने और यहां से आगे जाने में 1 घंटे से कम समय लगा। भगवान महाकाल की भस्म आरती के लिए रविवार रात 2.30 बजे ही

महाकाल मंदिर के पट खोल दिए गए। भस्म आरती में 17 हजार भक्तों ने भस्म आरती में दर्शन किए हैं। जबकि दोपहर बाद तक 2.15 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इधर, रायसेन के भोजपुर मंदिर में भगवान का 3 क्विंटल गुलाब, गेंदे, बिल्व पत्र, धतुरा और आम के पत्तों से श्रृंगार किया गया। ओंकारेश्वर में विशेष पूजा-अर्चना की गई। मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में शिव अभिषेक हुआ। आगर मालवा स्थित बाबा बैजनाथ का अर्धनारीश्वर स्वरूप में श्रृंगार हुआ।

बिजली विभाग कि बड़ी लापरवाही

सरपंच की शिकायत के बाद भी नहीं बदला गया ट्रांसफार्मर

सिटी चीफ बालाघाट, बिरसा जनपद पंचायत अन्तर्गत आने वाले ग्राम पंचायत झामूल के ग्राम सिल्हाटी टोला में विगत कई दिनों से अंधेरा पसरा हुआ है। जिस वजह से कृषि कार्य पुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं,रात में अंधेरा रहने कि वजह से जहरीले कीड़े व जहरीले सांप का भय बना रहता है,बच्चों कि पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। बिजली विभाग द्वारा खाना पुर्ती के लिए कम वोल्टेज का ट्रांसफार्मर लगा दिया गया था जो कुछ ही घंटे में जल गया जिसकी लिखित शिकायत ग्राम सरपंच गौतरिया मरावी द्वारा 10 जुलाई 2024 को मुख्य अभियंता अधिकारी बैहर से कि गई थी तथा इसकी शिकायत 1912 में भी दर्ज करवाई गई है,शिकायत को इतने दिन बित गये लेकिन नया हाई वोल्टेज वाला ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया है। इससे विधुत विभाग कि घोर लापरवाही सामने आ रही है विभाग द्वारा सरपंच कि शिकायत को नजर अंदाज कर दिया गया है तो आम आदमी कि शिकायत का क्या हाल होता होगा। साधारण व्यक्ति तो कार्यलय के चक्कर काटते काटते ही परेशान हो जाता होगा। वहीं शिकायत पत्र में उल्लेख है कि सिल्हाटी टोला में विगत दिनों से ट्रांसफार्मर खराब हो जाने के कारण ग्रामीण जनों को बारिश के चलते रात्रि कालीन रोशनी एवं कृषि कार्य करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ग्राम सिल्हाटी टोला में कुल 42 कृषकों का बोर कनेक्शन,70 परिवारों में घरेलू कनेक्शन व एक

राइस मिल है तथा वर्तमान में ट्रांसफार्मर कम वाट का होने के कारण लोडिंग अधिक हो रहा है। सहित अन्य समस्याओं का लिखित उल्लेख किया गया है। वहीं चर्चा में ग्राम सरपंच गौतरिया मरावी ने बताया कि मेरे द्वारा लिखित में बिजली विभाग को नया ट्रांसफार्मर लगाने हेतु शिकायत किया गया था,और मौखिक रूप से तो कई बार अवगत कराया गया है लेकिन अभी तक नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया है यदि कोई उपभोक्ता एक माह का बिजली बिल का भुगतान नहीं करें तो बिना शिकायत के लाईट काट दि जाती है,हम चाहते हैं कि अतिशीघ्र ही अविलंब गांव में ट्रांसफार्मर लगना चाहिए और ऐसे लापरवाह अधिकारी पर कार्यवाही होना चाहिए लापरवाही की हद होती है ।

कृषि कार्य सहित अन्य सभी कार्य हो रहे प्रभावित ज्ञात हो कि झामूल पंचायत अन्तर्गत आने वाले ग्राम सिल्हाटी टोला में ट्रांसफार्मर खराब होने से कृषि कार्य सहित अन्य सभी कार्य प्रभावित हो रहे हैं, ग्रामीण अधिकतर कृषि कार्य पर ही निर्भर रहते हुए अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए आ रहे हैं लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि यदि अतिशीघ्र ही नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया तो कृषि कार्य प्रभावित हो जायेगा धंधे चौपट हो रहे पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

अब देखना यह है कि कितने दिनों के भीतर इस गांव में नया ट्रांसफार्मर लगता है क्या ऐसे लापरवाह गैर जिम्मेदारों पर विभाग में बैठे उच्च अधिकारी कार्यवाही करेंगे या फिर ऐसे ही लापरवाही चलते रहेगी और लोगों को ऐसे ही गुमराह किया जायेगा आखिर कब तक ऐसा चलते रहेगा। वहीं हमारे द्वारा जब संबंधित अधिकारी से उनके दूरभाष नंबर 9425806227 पर उनका पक्ष रखने के लिए उनसे सम्पर्क किया गया तो घंटी जाने के बाद भी उनके द्वारा फोन नहीं उठाया गया फिर पुन: हमने उनसे सम्पर्क करने कि कोशिश कि तो यह महाशय का नंबर बंद बता रहा था। इससे साफ जाहिर होता है कि यह अपने काम के प्रति कितने इमानदार हैं।

जीडीसी प्राचार्या की सेवा बहाल हाई कोर्ट ने निलंबन आदेश किया निरस्त

शिकायतकर्ताओं की बिना साक्ष्य वाली शिकायत में हुई कार्यवाही

मोहम्मद मुनीर सिटी चीफ जब जब एक महिला अपने जीवकोपार्जन को घर की देहलीज़ से कदम बाहर निकलती है, इस दौरान कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से मिली सफलता हमारे पुरुष प्रधान देश में लोगो से हजम नहीं हो पाती कारण हद से अधिक ईर्ष्या द्य और कुछ नहीं उस पर से कुशल प्रबंधन में शीर्ष पदों में आसीन होने के बावजूद सेवा काल को सफलता पूर्वक बेदाग़ कर्तब्यो का निर्वाहन कर लेना आसान बात नहीं है लेकिन निम्न स्तर की राजनीति संभाग की एकलौती शासकीय शैक्षणिक संस्थान में सेवा प्रदान करने वाली महिला का सेवा निवृति से पूर्व गिरोह बनाकर दागी करार दे दिया, जबकि नारी शक्ति के उदाहरण स्वरुप लगातार इस महिला के शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा संचालित योजनाओ से छात्राओ को लाभान्वित करने का मामला हो या जीडीसी के उत्तरोत्तर आधुनिकीकरण से छात्राओ को अपडेट रखा जाने का मामला हो सतत अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाहन किया लेकिन इन सब बातो से कुंठित लोगो की मंशा एक नैतिक रूप से ताकतवर महिला की किसी भी तरह छवि को धूमिल कर दिया जाए।

शहडोल, जिला मुख्यालय स्थित शासकीय इंदिरा गाँधी गृह विज्ञान कन्या स्नात्तकोत्तर महाविद्यालय में लगातार चल रहे शिकवे शिकायतों का दौर हाई कोर्ट के संज्ञान लेते है थम गया, जिससे एक बार फिर जीडीसी की प्राचार्य उषा नीलम पदभार ग्रहण कर लिया है, गौरतलब हो की 6 सदस्यीय जनभागीदारी अतिथि विद्वानों ने दिनांक 24 अगस्त 2023 को तत्कालीन कलेक्टर वंदना वैध को टाइप शुदा एक शिकायती पत्र पर 13 करोड़ के मद का नियम विरुद्ध खर्च करना एवं चहेतो को प्राचार्या उषा

नीलम के द्वारा लाभान्वित किये जाने का हवाला देते हुए निलंबन किये जाने की कार्यवाही की बात कही, जिसमे शुरुवाती पत्र में ही बिना साक्ष्य दोषारोपण किया। संभवत: राजनितिक दबाव में अथवा अन्य कारणों से कलेक्टर ने इस पत्र के हवाले से जाँच खड़ी कर दी। जबकि लिखे गए पत्र में अनिमितताओं एवं भ्रष्टाचार से सम्बंधित कोई भी साक्ष्य का संलग्नीकरण शिकायतकर्ताओं ने नहीं किया था बावजूद निराधार गंभीर अपराध से सम्बंधित मामले को तूल पकड़ाया गया।

उच्च न्यायालय ने कहा.....

इस मामले में प्राचार्या को बेवजह चहुँतरफा परेशान किया गया, अंतत: प्राचार्या उषा नीलम को हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा, हालही में कोर्ट की हुए सुनवाई में कहा गया दिनांक 28.05.2024 के आदेश के तहत राज्य को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया था यह स्पष्ट है कि यदि सुनवाई की अगली तारीख पर या उससे पहले जवाब दाखिल नहीं किया जाता है, तो अंतरिम राहत पर विचार किया जाएगा। अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है, राज्य को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया है। इस मामले में याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील का कहना है कि आदेश निलंबन 30.01.2024 को जारी किया गया था और आरोप-पत्र हालांकि दिनांकित है 29.04.2024 लेकिन 11.05.2024 को भेजा गया यानी सीमा अवधि के बाद आरोप पत्र जारी करने के लिए विहित किया गया है, इसलिए निलंबन का आदेश दिया जाएगा निरस्त किया गया। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए निर्देशित किया जाता है कि आदेश दिनांक 30.01.2024 (अनुलग्नक-पी/एल) जिसके तहत याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया है सुनवाई की अगली तारीख तक रोक रहेगी। अंतरिम आदेश के क्रम में स्पष्ट करते हुए दिनांक 26.08.2024 को सूची जारी करें, आज मंजूरी दे दी गई, याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल किया जाएगा और अनुमति दी जाएगी, जिस पद पर वह मूल रूप से धारण कर रहा है, उस पद पर अगली तिथि तक कर्तव्यों का पालन करें।

क्यों बनी जबरन यह स्थिति.....

दरअसल शहडोल जिले में हर काम में अड़ंगा लगाने वाली

राजनीतो का शिकार शहडोल में महिलाये है शहडोल के पूर्व कुलपति मुकेश तिवारी के कार्यकाल में विधानसभा अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक शहडोल के पंडित शम्भूनाथ विश्व विद्यालय के चर्चा रही इस बात से अभी बखूबी वाकिफ है, एक बड़े पदों में रहने के बाद एक महिला प्राचार्या के नीचे रहकर कार्य करना किसी की भी ईगो को हर्ट कर सकता है, सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक यहाँ भी वही कहानी है। वरना ग्यारह साल को 13 वर्ष और लगभग साढ़े चार करोड़ रूपए आया मद में तेरह करोड़ की मनमर्जी कैसे हो जाती, संभावना यह भी जताई जा रही है आरोप गढ़ने वाले गिरोह ने कमजोर होम वर्क किया था जिसके चलते ही उच्च न्यायालय में मामला टिक नहीं सका। मामले में जानकार यह भी बताते है की शिकायत से लेकर आदेश तक पत्र में लगाए आरोप की पड़ताल की जाए तो मामले में कई पेच और आरोप लगाने वाले शिकायतकर्ताओं की नींद उड़ा सकता है। बिना दस्तावेज शासकीय इंदिरा गाँधी गृह विज्ञान कन्या स्नात्तकोत्तर महाविद्यालय के बच्चो एवं प्राचार्य का लगभग ग्यारह माह बर्बाद किया गया वो भी तब जब प्राचार्य को रिटायर्ड होने चंद दिन बचे है।

बैहर बंजर परियोजना कालोनी में अधिकारियों की लापरवाही के चलते ठेकेदार ने जमाया कब्जा

नियम को दरकिनार कर लगभग दो साल से अधिक समय से कर रहा शासकीय कालोनी में निवास

सिटी चीफ। बालाघाट, जिला मुख्यालय कि बैहर जनपद अन्तर्गत आने वाले बजंर नदी परियोजना संभाग के शासकीय कालोनी में ठेकेदार ने अधिकारियों से सांठगांठ कर कब्जा जमा लिया है,जानकारी अनुसार ठेकेदार अपने साथियों के साथ लगभग दो साल से अधिक समय से शासकीय नियमों को ठेंगा दिखाते हुए निवास करते हुए आ रहा है और संबंधित अधिकारी जानकर भी अनजान बने हुए हैं तथा कार्यवाही करने कि बजाय ठेकेदार को और छुट पर छुट दे रहे हैं।जिस वजह से ठेकेदार बेधड़क अपने साथियों के साथ मिलकर आराम से सरकारी कालोनी में निवास कर रहा है।

विदित हो कि नियम तो कहता है कि शासकीय आवास हो या फिर शासकीय कालोनी दोनों पर ही संबंधित अधिकारी या फिर उसका कर्मचारी जरूरत पड़ने पर निवास कर सकता है उसके लिए भी उच्च अधिकारियों को अवगत कराना पड़ता है कि संबंधित कर्मचारी निवास करेगा कहकर वह भी सीमित अवधि के लिए ही निवास कर सकता है ऐसा नियम कहता है यह हम नहीं कह रहे हैं और बाहर का कोई भी व्यक्ति शासकीय आवास या शासकीय कालोनी में निवास नहीं कर सकता है। लेकिन बैहर बंजर परियोजना के शासकीय कालोनी में तो ठेकेदार ने अपने साथियों के साथ में मिलकर कब्जा ही जमा लिया है वह भी दो साल से अधिक समय हो चुका है शायद ठेकेदार कि नियत उस शासकीय कालोनी में अपना कब्जा जमाने कि होगी तभी वह हट नहीं रहा है और संबंधित विभाग के अधिकारियों को उसको बोलने कि हिम्मत भी नहीं है कि अब शासकीय आवास खाली कर कहके सुत्रो से मिली जानकारी इसी ठेकेदार को शासकीय काम अधिक दिया जाता है क्योंकि यह ठेकेदार कमीशन अधिक देता है तभी तो बाहर का आया हुआ मामूली सा ठेकेदार आज बैहर का जाना-माना ठेकेदार बन गया है तथा शासकीय राशि से अपने साथियों के साथ मिलकर सरकारी चांदी काट रहा है और इसके द्वारा हर काम का अधिकारियों को भी आसानी से कमीशन पहुंचाया जा रहा है।

वहीं अब देखना यह है कि आखिरकार और कितने समय तक यह ठेकेदार शासकीय कालोनी में निवास करेगा,कब तक संबंधित अधिकारी शासकीय कालोनी से इसका कब्जा हटाते हैं या फिर जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देते हैं यह तो समय ही बताएगा कि क्या कार्यवाही संबंधित विभाग इस ठेकेदार पर करते हैं।या फिर खायेगा तो गायेगा वाली कहावत तो नहीं रहेगी यह तो भविष्य ही बताएगा।

डेथ पॉइंट बना मेडिकल कॉलेज चौक, महिला डॉक्टर की मौत

ट्रक के पहिये में फसी, दूर तक घसीट गई स्कूटी

मोहम्मद मुनीर । सिटी चीफ शहडोल, शासकीय बिरसा मुण्डा चिकित्सा महाविद्यालय मे प्रशिक्षु एक महिला चिकित्सक बीते सोमवार दोपहर एक बड़े सडक हादसे का शिकार हो गई। वह स्कूटी समेत ट्रक के पहिए मे फंसने के बाद लगभग चालीस मीटर तक घसिटती रहीं और अंत मे फिर सडक से दूर जा फेंकाई। घटना के बाद चिकित्सक को गंभीर हालत मे मेडिकल कॉलेज मे भर्ती कराया गया है। जहाँ गहन चिकित्सा यूनिट मे उनका इलाज चल रहा है। इस संबंध मे मिली जानकारी के अनुसार मेडिकल कॉलेज मे प्रशिक्षु चिकित्सक के रूप मे पदस्थ सृष्टि सोनी सोमवार को ड्यूटी करने के बाद दोपहर लगभग 2 बजे अपनी स्कूटी क्रमांक एमपी 65 जेडए 2318 से घर जा रहीं थी। जैसे ही वह मेडिकल कॉलेज चौराहा से हाइवे मे पहुंची तभी बुढ़ार की ओर से तेज रफ़्तार आ रहे ट्रक क्रमांक टीएन 46 एस 6369 की चपेट मे आ गई। जिसके बाद वह स्कूटी समेत ट्रक के पहिये मे फंस गई। और करीब 40 मीटर तक घसिटने के बाद सडक मे दूर फेंका गई। जबकि स्कूटी अब भी ट्रक के पहिए मे फंसी हुई थी। वहाँ आसपास मौजूद लोगो द्वारा ट्रक चालक को इशारा करते हुए वाहन रोकने को कहा। लेकिन उसने ट्रक नही रोका। लगभग आधा किलोमीटर तक स्कूटी को वह घसीटता हुआ आगे ले गया। ज़ब पुलिस के डायल 100 ने ट्रक का पीछाकर उसे रुकवाया तब जाकर ट्रक के पहिए थमे। थाना प्रभारी सोहागपुर भूपेंद्र मणि पांडे ने बताया कि ट्रक चालक को हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है ट्रक को थाने में लाकर खड़ा कराया है।

मीडिया ने किया था आगाह....

उक्त मेडिकल कॉलेज चौराहा डेथ पॉइंट बन चुका हैं। हादसे के कारण अब तक कई लोग वहाँ अपनी जान गँवा चुके है। जबकि कई लोगो के हाथ पैर फैक्चर हुए हैं। लेकिन लगातार हादसे के बाद न तो सडक निर्माण से जुड़े विभाग ने इस ओर आज तक ध्यान दिया और न ही प्रशासन के आला अधिकारियों को इन हादसों से कोई फर्क पड़ा। हाँ जिन लोगो ने असमय यहाँ हादसों मे अपनों को खोया हैं, आज भी उनके दर्द कम नही हुए हैं। पूर्व मे हुए हादसे के बाद ज़ब काफी हो हल्ला हुआ और इस संबंध मे मीडिया मे खबरे प्रकाशित हुई तब अस्थाई तौर पर यातायात उप पुलिस अधीक्षक द्वारा बैरिकेट्स रखवा दिया गया था। लेकिन वह इन हादसों को रोकने मे कारगर साबित नही हुआ। क्योकि रात्रि मे वहाँ से तूफ़ानी रफ़्तार से गुजरने वाले ट्रक व अन्य बड़े वाहनो द्वारा बैकेट्स को टक्कर मार तोड़ दिया जाता है। उक्त चौराहे मे हादसे को रोकने स्थाई व्यवस्था करने की जरूरत हैं। अब प्रशासन आगे कुछ उपाय करता हैं अथवा इसी तरह लोगो को हादसे का शिकार होने के लिए छोड़ देगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा।

प्रतिक्रिया.....

इंटर्नशिप कर रही डॉक्टर सृष्टि सोनी को सड़क हादसे में गंभीर चोट पहुंची है, उनके सर में गंभीर चोट है, मुझे जब जानकारी लगी तो मैं खुद जाकर उन्हें देखा हूं, डॉक्टर की टीम उनका इलाज कर रही है।- डॉक्टर नगेंद्र सिंह, मेडिकल कॉलेज अधीक्षक बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल

प्रतिशोध में हुई वारदात 70 वर्षीय की हत्या

जयसिंहनगर थाना क्षेत्र के ग्राम टेटका मे हुई वारदात

मोहम्मद मुनीर । सिटी चीफ

शहडोल, पिता की मौत के पीछे जादू टोना का शक पुत्र के दिमाग मे इस कदर बैठा कि उसने पड़ोस मे रहने वाली महिला रिश्ते की दादी को पीट पीटकर मौत के घाट उतार दिया। यह घटना जयसिंहनगर थाना क्षेत्र के ग्राम टेटका घटित हुईं। जानकारी के अनुसार जयसिंहनगर थाना क्षेत्र के ग्राम टेटका निवासी रामसुर गोंड़ 60 वर्ष की मौत हो गई। पता चला हैँ कि वह कैसर जैसी घातक बीमारी से पीड़ित थे। लेकिन मृतक के पुत्र राजू सिँह गोड़ को काफी समय से इस बात का शक था कि पड़ोस मे रहने वाली दादी सुभागिया पति रामसेवक उम्र 70 वर्ष द्वारा उसके पिता के ऊपर जादू टोना किया गया हैँ। और इसी कारण इस घातक बीमारी की चपेट मे आने के बाद उनकी मौत हुईं है। बीते देर शाम पिता की मौत के कुछ ही देर बाद वह उक्त महिला के घर पहुंच गया। जहाँ राजू ने महिला को पटक पटक कर मारा और ज़ब महिला अचेत हो गई तो उसे लगा की वह मर चुकी हैँ तो वहाँ से भाग गया। घटना के बाद वृद्धा को गंभीर हालत मे जयसिंहनगर अस्पताल लाया गया, जहाँ कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। मृतिका के परिजनों के अनुसार राजू के पिता काफी समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहें थे। उन्हें कैसर भी हो गया था। इस लाइलाज बीमारी के कारण ही उनकी मौत हुईं हैँ। लेकिन उनके पुत्र ने जबरन जादू टोना के शक में वारदात को अंजाम दिया है।

एक तरफ पीएम तो दूसरी तरफ अंतिम संस्कार की तैयारी

इस वारदात के बाद गाँव मे सन्नाटा पसरा हुआ है। एक तरफ जहाँ वृद्धा की हत्या के बाद पुलिस द्वारा उसका पोस्ट मार्टम कराया जा रहा हैँ, वहीं दूसरी ओर आरोपी राजू के पिता के अंतिम संस्कार की तैयारिया चल रही है। गाँव मे एक साथ दो पड़ोसियों की मौत के बाद मातम पसरा हुआ है। बहरहाल पुलिस अब राजू के पिता के अंतिम संस्कार के बाद उसे गिरफ्तार करने की बात कह रही हैँ।

प्रतिक्रिया .....

आरोपी के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया गया है, जादू टोना की बात को लेकर हत्या हुई है जांच चल रही है। **सतेंद्र चतुर्वेदी, थाना प्रभारी, थाना - जयसिंहनगर**

अवैध रूप से चल रही पैथालाजियो पर नहीं हो रही कार्यवाही

जिम्मेदारो ने साध रखी है चुप्पी, लुट रहे मरीज

ब्योहारी, नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रो मे जगह - जगह अवैध रूप से पैथालॉजी संचालित है जिसकी जानकारी जिम्मेदार अधिकारी को भी है किन्तु ऐसा लग रहा है जैसे वो अपना कमीशन लेकर मानो आंख मे पट्टी बांध ली हो। अवैध तरीके से चल रही पैथालॉजी के संबंध मे समाचार भी प्रकाशित हुआ किन्तु अधिकारियो के कान मे जू तक नहीं रेगा और वो आज भी कुम्भ करणीय निद्रा मे सो रहे है। कोई जिये या मरे उन्हें तो सिर्फ कमीशन से मतलब है। अवैध रूप से चल रही पैथालाजी के संबंध मे कमिश्नर बी. एस. जमोद द्वारा भी कार्यवाही करने का आदेश विगत दिनों बैठक मे जिला चिकित्सा अधिकारी को दिया गया किन्तु यंहा उनके आदेश का भी पालन होता नहीं दिख रहा है, आलम यह है कि ब्योहारी क्षेत्र अंतर्गत नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रो मे जगह - जगह अवैध पैथालॉजी का संचालन धड़ल्ले किया जा रहा है। अवैध रूप से चल रहे इन पैथालॉजियों की जानकारी क्या यंहा के खंड चिकित्सा अधिकारी को नहीं है? सायद यह कहना गलत होगा क्योंकि सामुदायिक स्वाथ्य केंद्र ब्योहारी के सामने ही दर्जनों पैथालॉजी संचालित है और ऐसा नहीं है कि वंहा से आते जाते उन पैथालॉजियों पर उनकी नजर न पड़ती हो। जानकारों द्वारा कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे जिम्मेदार अधिकारी अपना कमीशन लेकर उन अवैध पैथालॉजियो के संचालको को पैथालॉजी का संचालन करने की खुली छूट दे रखी हो। ताज्जुब की बात यह है कि बिना अनुमति और मान्यता के संचालित इन केन्द्रो के विरुद्ध कार्यवाही करने से परहेज क्यों किया जा रहा है।

जबकी नियमानुसार प्रशासन को इन अवैध पैथालॉजी पर शिकंजा कस देना था, ताकि आम जनता का शारीरिक और आर्थिक शोषण रोका जा सके। गौरतलब है कि प्रशासनिक अनदेखी के चलते नगर से लेकर गांव तक बिना पैथालॉजिस्ट और बिना रजिस्टेसन के अवैध पैथालॉजी संचालित हो रही है।सूत्रों की माने तो इनके पास मेडिकल बेस्ट और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं है। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग द्वारा इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है। जिला स्वास्थ्य विभाग की माने तो यंहा संचालित कोई भी पैथालॉजी अभिलेखों मे दर्ज नहीं है। कार्यवाही नहीं होने की वजह से अवैध लैब संचालको के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि लैब में मरीजों का खुले आम खून चूसा जा रहा है।

नियमों की अनदेखी -

जानकारों के मुताबिक पैथोलॉजी जांच की रिपोर्ट को प्रमांणित करने क लिए एमसीआई (मेडिकल काउन्सिल ऑफ इडिया) द्वारा पंजीकत तथा पोस्ट ग्रेज्युएट डिग्रीधारक चिकित्सक को ही अधिकृत माना है। इसके साथ ही लैब में योग्यताधारी लैब टेक्नीशियन पदस्थ होना जरूरी है।जबकि ब्योहारी में नॉन पैथोलॉजिस्ट तथा झोलाछाप चिकित्सा कर्मी भी खून,पेशाब,खंगार का नमूना लेकर जांच रिपोर्ट दे रहे हैं।जो गलत होने के साथ स्वास्थ्य अधिनियम का भी खुला उलंघन्न है। इसके पालन नहीं करने पर कैद और जुर्माना का प्रावधान है।

अप्रशिक्षित के हाथो बन रही रिपोर्ट -

किसी भी पैथालॉजी में मापदंड का पालन नहीं किया जा रहा।लिहाजा नमूना एकत्र करने से लेकर जांच रिपोर्ट जारी करने का काम अनाड़ियों के हांथों में ही है।ऐसी दशा मे जांच रिपोर्ट की विश्वसनीयता भी सवालों के घेरे में है। आलम यह है कि अधिकांश जांच घरों में अप्रशिक्षित कर्मियों द्वारा ही मरीजों का खून, पेशाब व अन्य जांच की जा रही है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इसी आधार पर चिकित्सकों द्वारा मरीजों का ईलाज और दवा लिखी जा रही है। जिसका आर्थिक,शारीरिक और मानसिक खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है।इस बाबद प्रशासन भी गंभीरता नहीं दिखा रहा है।

योग्यता और रजिस्टेशन दर किनार -

लैब संचालन के लिये शासन द्वारा विधिवत नियम लागू किये गये है, लेकिन आश्चर्य जनक रूप से डीएमएलटी व उनके सहयोगी तक लैब संचालित कर रहे है वो ही रिपोर्ट मे साइन करके दे रहे है जबकी लैब संचालक एमबीबीएस, एमड़ी पैथालॉजिस्ट होना चाहिए। इतना ही नहीं अवैध तरीके से संचालित हो रहे लैबो के पास न ही नियमानुसार पाल्यूशन बोर्ड का रजिस्टेशन और न ही पंजीकृत मेडिकल वेस्ट फर्म का पंजीयन है।

इनका कहना है -

प्रतक्रिया के लिये फोन लगाया गया किन्तु उनके द्वारा फोन नहीं उठाया गया।

ओ. पी. चौधरी , खंड चिकित्सा अधिकारी ब्योहारी

पूरा जिला देखना पड़ता है। कल जयसिंहनगर मे जांच हुई है। आज गोहपारू मे हूँ। अब ब्योहारी का ही नंबर है।

डॉ. अशोक लाल , जिला चिकित्सा अधिकारी शहडोल

जमीनी विवाद में तलवारबाजी समधी की मौत

बहु की हालत गंभीर, उपचार के लिए रीवा भेजा गया

मोहम्मद मुनीर । सिटी चीफ

शहडोल, ज़मीन जायज़ाद के बटवारे को लेकर उपजे विवाद के बाद ससुर ने अपने समधी व बहू के ऊपर तलवार से हमला कर दिया। जिसमे समधी की मौत हो गई, जबकि बहू की हालत गंभीर बताई जा रही है जिसे उपचार के लिए रीवा भेजा गया है। घटना जिले के पपौंध थाना क्षेत्र के ग्राम तिखवा मे रविवार शाम लगभग पांच 5 बजे घटित हुईं। जानकारी के अनुसार ग्राम तिखवा निवासी राजेंद्र गुप्ता 50 वर्ष एवं उसकी बहू प्रभा गुप्ता पति नितेश गुप्ता उम्र 26 वर्ष के बीच आए दिन विवाद होता था। जिसके बाद पिछले आठ माह से बहू अपने पति के साथ घर मे ही अलग रहकर खाना बनाती थी। लेकिन इसके बावजूद बहू एवं ससुर के बीच संपत्ति बटवारे को लेकर आए दिन विवाद होता रहता था।

दरअसल शनिवार को भी इसे लेकर बहू और ससुर के बीच विवाद हुआ। जिसके बाद बहू ने अपने पिता रामाश्रय गुप्ता 52 वर्ष निवासी ताला मझौली जिला सीधी को तिखवा आकर ससुर से जायज़ाद का बटवारा कराने की बात कही। जिसके बाद आज रविवार को प्रभा (बहू)के पिता अपने पुत्र विवेक के साथ समधीयाने ग्राम तिखवा पहुंचे। सुबह से लेकर शाम तक ज़मीन, जायजाद व जेवर का बटवारा होता रहा। लेकिन शाम होते होते फिर किसी बात को लेकर बहू के पिता रामाश्रय व ससुर राजेंद्र के बीच विवाद शुरू हो गया। जिसके बाद राजेंद्र ने घर मे रखी एक पुरानी तलवार निकाली और समधी व बहू के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। तलवार के साथ साथ पत्थर से भी कई वार किए। इस हमले मे समधी रामाश्रय की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। जबकि गंभीर रूप से घायल बहू को प्राथमिक उपचार के बाद ब्योहारी भेज दिया गया। जहाँ उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे रीवा रेफर कर दिया गया है।

प्रतिक्रिया ....

बहू की हालत गंभीर है हंड्रेड डायल से उसे ब्यौहारी अस्पताल भिजवाया था जिसे डॉक्टर ने रीवा रेफर कर दिया है, एक की मौके पर मौत हुई है, आरोपी को पुलिस में अपने हिरासत में ले लिया है।

एम एल वर्मा थाना प्रभारी थाना पपौंध, शहडोल

उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के त्रिवार्षिक चुनाव संपन्न

अश्वनी मित्तल अध्यक्ष, सतवीर चौधरी महामंत्री मोहम्मद वरयाम खान कोषाध्यक्ष हुए निर्वाचित

सहारनपुर । देवबंद, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का त्रिवार्षिक चुनाव कार्यक्रम जनता इंटर कॉलेज के प्रांगण में चुनाव अधिकारी ईश्वर दयाल एवं जिलाध्यक्ष शीतल टंडन की मौजूदगी में संपन्न हुआ। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष, महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष का चुनाव हुआ। जिसमें अश्वनी मित्तल अध्यक्ष, सतवीर चौधरी महामंत्री और मोहम्मद वरयाम खान कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए। व्यापार मंडल के चुनाव में निर्वाचित हुए पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए जिलाध्यक्ष शीतल टंडन ने संगठन को मजबूत करने, व्यापारियों की समस्याओं को निस्तारित कराने एवं सरकार के कानून एवं नियमों में व्यापारी का अहित न हो इसका हर संभव ध्यान रखने, व्यापारी समाज की मांगों को प्रशासन एवं उनके माध्यम से शासन तक पहुंचाने का कार्य सर्वोपरि रखने का सुझाव दिया गया। जिलाध्यक्ष शीतल टंडन ने जिले की ओर से नगर के प्रभारी के रूप में राजन छाबडा को मनोनीत करते हुए कहा गया कि संगठन के कार्यों में जिले का प्रतिनिधित्व राजन छाबड़ा द्वारा किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक राज सिंघल ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए निवर्तमान अध्यक्ष अरुण गुप्ता के कार्यकाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके द्वारा व्यापारियों की समस्याओं को हल करने का हर संभव कार्य किया गया।

उनके द्वारा व्यापार मंडल को एकजुट रखते हुए संगठन का विस्तार एवं व्यापारियों की समस्याओं का निदान करने का कार्य भी किया गया। जिसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि आशा है कि नवनिर्वाचित पदाधिकारी भी इसी प्रकार कार्य करते हुए मजबूती से व्यापारी समाज की समस्याओं का निदान करने का प्रयास करेंगे। निवर्तमान अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए जल्द संगठन की मजबूत कार्यकारिणी गठन करने का सुझाव देते हुए व्यापारी हित में कार्य करने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार की नीतियां व्यापारी हित में सदैव रही है और सरकार का हर संभव प्रयास व्यापारियों को सुरक्षा एवं भय मुक्त होकर व्यापार करने का रहा है। इस अवसर पर संरक्षक मंडल विजेश कंसल, विजय गिरधर, महेंद्र गिरधर द्वारा भी शाब्दिक शुभकामनाएं देते हुए व्यापार मंडल को मजबूत करने की अपील की। इस अवसर पर अर्जुन सिंघल, विकास पुंडीर, रविंद्र चौधरी, अनुज गर्ग, अमित सोनी, शिवनंदन, राजीव राणा, अमित चौधरी, पवन धीमान, मोहम्मद वसीम, मनीष अग्रवाल, नीरज जैन, हरविंदर सिंह बेदी, नीरज अग्रवाल, राजीव शर्मा, हिमांशु सिंघल, देवी दयाल शर्मा, देवी दयाल गर्ग आदि उपस्थित रहे।

बच्चों से उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को जानने के लिए संवाद कार्यक्रम आयोजित

कार्यक्रम में प्रधान मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त राघवेंद्र मीणा सुषमा बड़ोनिया, सीमा शर्मा आदि उपस्थित थे

भगवान दास बैरागी । सिटी चीफ

शाजापुर, किशोर न्यायबोर्ड जिला शाजापुर के समक्ष प्रस्तुत होने वाले बच्चों से उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को जानने के लिए सोमवार को संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। संवाद के दौरान बच्चों ने अपनी समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया। उनकी समस्याओं में एक प्रमुख समस्या सामने आई कि बाल अपचारी बच्चों से कोई भी अपराध होने पर उन्हें संबंधित स्कूलों से स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी दे दिया जाता है या उन्हें स्कूल से स्वयं टीसी लेने से बाध्य किया जाता है या निष्कासित किए जाने की धमकी दी जाती है, जो कि उक्त बच्चों के साथ क्रूरता की श्रेणी में भी आती है। ऐसा किए जाने पर किशोर न्याय अधिनियम या बालकों की देखरेख एवं संरक्षण 2015 के अनुसार दंडनीय अपराध है। इसके बारे में विस्तार से उन्हें जानकारी प्रदान की गई और बताया कि कोई भी स्कूल संचालक किसी बाल अपचारी को इस प्रकार से स्कूल से नहीं निकाल सकते और उनकी शिक्षा को निरंतर जारी रखने से नहीं रोक सकते हैं। मौके पर मौजूद प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्यायबोर्ड शाजापुर डॉ स्वाति चौहान ने बताया कि कोई भी स्कूल संचालक किसी भी बाल अपचारी बच्चे को उसकी शिक्षा निरंतर रखने से नहीं रोक सकते हैं। यदि कोई भी स्कूल संचालक किसी बाल अपचारी को उसकी शिक्षा को नियमित रखे जाने से रोकते हैं तो स्कूल संचालक प्रभारी के विरूद्ध किशोर न्याय अधिनियम या बालकों की देखरेख एवं संरक्षण 2015 के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जा सकती है। उक्त संवाद में प्रधान मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त राघवेंद्र मीणा, सुषमा बड़ोनिया, सीमा शर्मा आदि उपस्थित थे।

संस्कृत में छात्रों को श्लोक बोलने से रोकने वाली प्राचार्या पर हुई एफआईआर

विद्यार्थी परिषद और हिन्दूवादी संगठनों ने वंदना कॉन्वेंट स्कूल गेट पर किया जमकर प्रदर्शन, भारी पुलिस बल तैनात

गुना। शहर के निजी स्कूल वंदना कॉन्वेंट में प्रार्थना के दौरान छात्रों को संस्कृत का श्लोक बोलने से रोकने पर सोमवार को जमकर बवाल हुआ। एक दिन पूर्व जहां मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस थमाया। वहीं मामले में सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विहिप एवं बजरंगदल ने स्कूल गेट के आगे जमकर प्रदर्शन किया। मामले में कोतवाली पुलिस ने परिषद कार्यकर्ता की शिकायत पर स्कूल प्राचार्य के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। दरअसल विगत 15 जुलाई को वंदना कॉन्वेंट स्कूल के छात्र ध्रुव पलिया, गौरव किरार और रश वर्मा द्वारा हिन्दू संस्कृति के स्पीच की शुरुआत सर्वे भवन्तु सुखना अनुसार संस्कृत में सर्वे भवन्तु सुखमया के साथ की थी। इतने में वंदना स्कूल की प्राचार्या सिस्टर कैथरीन ने नाराज होकर बच्चे से माईक छुड़ा लिया और उसे स्पीच देने से रोक दिया।

डीएम ने तहसील सदर में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में सुनी समस्याएं

प्रकरणों को गम्भीरता से सुनते हुए समय सीमा के अन्दर करें निस्तारित – डीएम मनीष बंसल

गौरव सिंघल । सिटी चीफ
सहारनपुर, जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा तहसील सदर में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में आए हुए लोगों की शिकायतों को सुनकर सम्बन्धित अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की मंशा के अनुरूप जो समय सीमा समस्याओं के निस्तारण की दी गई है, उसी के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराएं। उन्होंने यह भी कहा कि निस्तारण के साथ-साथ लाभार्थी को संतुष्टी भी मिलनी चाहिए। यदि किसी शिकायत का निस्तारण नहीं हो सकता तो उसके बारे में भी शिकायतकर्ता को कारण सहित बताया जाए। डीएम मनीष बंसल ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जन शिकायतों का निस्तारण मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में शामिल है। प्राप्त शिकायतों को निर्धारित समय में संवेदनशीलता अपनाते हुए गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारित करें। शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वालों के विरूद्ध कडी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायत निस्तारण के प्रति संवेदनशीलता दिखाएं और मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए समस्याओं का समयबद्धता से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। डीएम मनीष बंसल ने कहा कि योजनाओं का लाभ पात्रों को दिलाने में लापरवाही न बरती जाएं। उन्होंने दिव्यांगजन अधिकारी, प्रोबेशन अधिकारी एवं समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि पात्रों को नियमानुसार समय से पेंशन एवं अन्य विभागीय योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। वृद्ध एवं दिव्यांगों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जाए। उन्होंने अनुपस्थित अधिकारियों के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए सख्त निर्देश दिए कि जिला स्तरीय अधिकारी सम्पूर्ण समाधान दिवस में अनिवार्य रूप से उपस्थित हो। इसी के साथ प्रतिदिन अपने कार्यालय में प्रात: 10:00 से 12:00 बजे तक जनसुनवाई करते हुए शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। सम्पूर्ण समाधान दिवस में राजस्व विभाग की 12, पुलिस विभाग की 05, नगर निगम की 08, विद्युत विभाग की 04 एवं अन्य 08 कुल 37 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 03 मौके पर ही निस्तारित कर दी गयी। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 प्रवीण कुमार, उपजिलाधिकारी सदर युवराज सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर रूचि गुप्ता, तहसीलदार सदर अमित कुमार सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

डीएम ने किया घण्टाघर चौक पर कांवड मार्ग का निरीक्षण

जनपद स्तरीय अधिकारी कांवड यात्रा को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु सौंपे गये उत्तरदायित्वों का भली प्रकार से करें निर्वहन :- डीएम मनीष बंसल

गौरव सिंघल । सिटी चीफ
सहारनपुर, जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा आगामी कांवड-यात्रा को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु कावड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत घण्टाघर चौंक पर मुख्य कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी मनीष बंसल ने श्रद्धालुओं के आवागमन के दृष्टिगत सभी आवश्यक व्यवस्थाएं निरंतर बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि कांवड यात्रा को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु सौंपे गये उत्तरदायित्वों का भली प्रकार से निर्वहन करें। उन्होंने निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पडे। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन, एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक, एसपी यातायात सिद्धार्थ वर्मा, सिटी मजिस्ट्रेट गजेन्द्र कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी उपस्थित रहे।

डीएम ने किया निर्माणाधीन मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का औचक निरीक्षण

अतिरिक्त श्रमिक लगाकर कार्य को गुणवत्तापरक एवं शीघ्रता से करें पूर्ण अधिशासी अभियन्ता लोनिवि प्रतिदिन उपलब्ध कराएं प्रगति रिपोर्ट

गौरव सिंघल । सिटी चीफ
सहारनपुर। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने निर्माणाधीन मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कार्य की धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि बचे हुए कार्यों को अतिरिक्त श्रमिक लगाकर गुणवत्तापरक एवं शीघ्रता से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने संबंधित संस्था को कहा कि बहाना न बनाते हुए कार्ययोजना तैयार कर कार्य को समय से पूर्ण करें। डीएम मनीष बंसल ने अधिशासी अभियन्ता लोनिवि को निर्देश दिए कि प्रतिदिन उपस्थित होकर कार्य में हुई प्रगति से अवगत कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने विश्वविद्यालय में पानी की निकासी, सौन्दर्यीकरण के कार्य तथा सभी लम्बित कार्यों को समय से पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों के समय से पूर्ण न होने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने विश्वविद्यालय निर्माण कार्य से संबंधित संस्थाओं लोनिवि, पीएमसी एवं ठेकेदार को निर्देश दिए कि सभी सौंपे गये उत्तरदायित्वों को जिम्मेदारी से निभाएं। विश्वविद्यालय परिसर में अधिक से अधिक पौधरोपण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर कुलपति प्रो0 हृदय शंकर सिंह, मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन, रजिस्ट्रार वीरेन्द्र कुमार मौर्य सहित कार्यदायी संस्था के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

वंचित बहुजन आघाडी जनुना ग्रामपंचायत मध्ये धुवा बीजेपीला यश प्राध्यापक मधुकर पवार यांनी घेतली दखल

डॉ संजय चव्हाण । सिटी चीफ जनुना येथील नवनिर्वाचित उपसरपंच श्री.विजय जाधव यांच्या सह श्री.अजय जाधव,श्री.रोहित पवार,श्री.संजय पवार भारतीय जनता पक्षात पक्ष प्रवेश मंगळवार दिनांक 16/07/2024 रोजी जनुना येथील नवनिर्वाचित उपसरपंच श्री.विजय जाधव, श्री.अजय जाधव, श्री.रोहित पवार,श्री.संजय पवार यांनी बार्शीटाकळी येथे मुर्तिजापूर विधानसभा मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार हरीषभाऊ पिंपळे यांच्या नेतृत्वात भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. याप्रसंगी आमदार श्री.हरीषभाऊ पिंपळे यांनी पक्ष प्रवेश करणाऱ्या सर्व कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन करून पुढील राजकीय व सामाजिक वाटचालीस शुभेच्छा व्यक्त केल्या. यावेळी भाजप तालुका अध्यक्ष बार्शीटाकळी श्री.संजय पाटील इंगळे, भाजयुमो तालुका अध्यक्ष श्री.संदिप राठोड जिल्हा परिषद सदस्य श्री.रायसिंग राठोड, पंचायत समिती उपसभापती श्री.संजय चौधरी,भाजप शहराध्यक्ष बार्शीटाकळी प्रविणभाऊ धाईत, पंचायत समिती सदस्या सौ.संगीताताई जाधव,राम पाटील आंबेकर,सुधाकर महल्ले, निलेश हांडे, भाजप तालुका प्रसिध्दी प्रमुख वैभव पाठे पाटील यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.

भारत में तेजी से हो रहा है वित्तीय समावेशन

किसी भी देश में वित्तीय समावेशन के बढ़ने का आशय यह है कि उस देश के नागरिकों की उस देश के बैंकिंग संस्थानों तक पहुंच बढ़ रही है और यह उस देश की अर्थव्यवस्था के औपचारीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक एवं पेन्शन क्षेत्र के हितधारकों को शामिल करते हुए वित्तीय समावेशन सूचकांक विकसित किया है। दरअसल, भारत में विभिन्न क्षेत्रों में हो रही अतुलनीय प्रगति को दशार्ने के लिए अब अपने सूचकांक विकसित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है क्योंकि वैश्विक स्तर पर वित्तीय एवं आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत विदेशी संस्थानों द्वारा विकसित किए गए सूचकांकों के आधार पर किए जाने वाले सर्वे में तो विभिन्न क्षेत्रों में भारत की प्रभावशाली प्रगति की सही तस्वीर पेश नहीं की जा रही है। इन सूचकांकों के आधार पर किए गए कई सर्वे में तो आश्चर्यजनक परिणाम दिखाई देते हैं। जैसे, एक सर्वे में भुखमरी के क्षेत्र में भारत की स्थिति को अफ्रीकी देशों, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बंगलादेश से भी बदतर बताया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विकसित किए गए वित्तीय समावेशन सूचकांक के आधार पर मार्च 2024 के परिणाम हाल ही में जारी किए गए हैं। इन परिणामों के अनुसार, भारत में वित्तीय समावेशन मार्च 2017 में 43.4, मार्च 2021 में 53.9 एवं मार्च 2023 में 60.1 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2024 में 64.2 प्रतिशत हो गया है। यह सूचकांक भारत में वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में हुई अतुलनीय एवं स्थिर प्रगति को दशार्ता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विकसित किया गया यह सूचकांक वित्तीय समावेशन के विभिन्न आयामों (नागरिकों की वित्तीय संस्थानों पर बढ़ती पहुंच, वित्तीय उत्पादों का बढ़ता उपयोग एवं वित्तीय सेवाओं की गुणवत्ता) पर देश में वित्तीय समावेशन के संदर्भ में जानकारी को 0 से 100 तक के मान में बताता है। यदि मान कम है तो देश में वित्तीय समावेशन भी कम है और इसके विपरीत यदि मान अधिक है तो देश में वित्तीय समावेशन भी अधिक है। भारत में यह मान मार्च 2024 में बढ़कर 64.2 प्रतिशत हो गया है। उक्त वर्णित तीन आयामों में कई पैरामीटर शामिल हैं, इनका मूल्यांकन 97 संकेतकों के आधार पर किया जाता है। इस कार्यप्रणाली के कारण ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विकसित किया गया यह सूचकांक वित्तीय समावेशन का एक व्यापक संकेतक बन गया है। वित्तीय समावेशन सूचकांक प्रत्येक वर्ष के जुलाई माह में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। किसी भी देश में वित्तीय समावेशन के बढ़ने का आशय यह है कि उस देश के नागरिकों की उस देश के बैंकिंग संस्थानों तक पहुंच बढ़ रही है और यह उस देश की अर्थव्यवस्था के औपचारीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। वर्ष 2014 में भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना को लागू किया गया था और इस योजना के अंतर्गत विभिन्न बैंकों में गरीब वर्ग के जमा खाते खोलकर उन्हें वित्तीय समावेशन का हिस्सा बना लिया गया था। आज प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत लगभग 52 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं एवं इन जमा खातों में लगभग 2.35 लाख करोड़ रुपए की राशि जमा है। केंद्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा देश के गरीब वर्ग को दी जाने वाली सहायता/प्रोत्साहन राशि को भी इन खातों में आज सीधे ही जमा कर दिया जाता है, इसे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के रूप में भी जाना जाता है, जिससे इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार लगभग समाप्त हो गया है क्योंकि इससे अंतत: लीकेज कम हुए है और यह सुनिश्चित हुआ है कि योजनाओं का लाभ अंतिम लाभार्थी तक सीधे ही पहुंचे। प्रधानमंत्री जनधन योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य भारत के दूर दराज के इलाकों में निवासरत नागरिकों को बैंकिंग, बचत और जमा खाते, राशि हस्तांतरण, ऋण, बीमा और पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध कराना था। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रधानमंत्री जनधन योजना पूर्ण रूप से सफल रही है और भारत में वित्तीय समावेशन को अगले स्तर पर ले जाने में भी सहायक रही है। साथ ही, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए जमा खातों को भारत की विशिष्ट पहचान प्रणाली (आधार कार्ड) से जोड़कर, केंद्र सरकार ने देश में वित्तीय लेन देन प्रणाली को सुव्यवस्थित कर लिया है एवं बैंकिंग व्यवहारों में धोखाधड़ी की सम्भावना को कम करने में भी सफलता अर्जित की है। आज भारत की प्रधानमंत्री जनधन योजना को पूरे विश्व में सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना के रूप में पहिचान मिली है। देश में प्रधानमंत्री जनधन योजना को आज भी वित्तीय समावेशन के मुख्य उपकरण के रूप में माना जा रहा है और इस योजना के अंतर्गत देश के नागरिकों के खाते विभिन्न बैंकों में उसी उत्साह से लगातार खोले जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी भारत के विभिन्न बैंकों में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत लगभग 3.3 करोड़ नए जमा खाते खोले गए हैं इससे इस योजना के अंतर्गत खोले गए कुल खातों की संख्या बढ़कर 51.95 करोड़ हो गई है एवं इन जमा खातों में 234,997 करोड़ रुपए की राशि जमा हो गई है। अब देश का एक गरीब नागरिक भी भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। वित्तीय समावेशन के दायरे में लाए गए नागरिक वित्तीय क्षेत्र में साक्षर होने के पश्चात अब तो भारत के पूंजी बाजार (शेयर बाजार) में भी अपना निवेश करने लगे हैं एवं उनकी विभिन्न ऋण योजनाओं एवं बीमा उत्पादों तक पहुंच भी बढ़ गई है। वित्तीय सेवाओं तक इस पहुंच ने देश के नागरिकों को आर्थिक रूप से बहुत सशक्त बना दिया है, इससे अंतत: यह नागरिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं छोटे व्यवसायों में निवेश करने में सक्षम हुए हैं और इस प्रकार इन नागरिकों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार हुआ है। भारत में वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में हुई उक्त वर्णित अतुलनीय प्रगति की जानकारी हम आम नागरिकों को तभी मिल पा रही है जब भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में ही एक सूचकांक विकसित किया है। यदि वित्तीय समावेशन का सूचकांक किसी विदेशी संस्थान द्वारा तैयार किया जाता तो सम्भव है कि भारत की इस महान उपलब्धि को जानने से हम वंचित रह जाते। अब समय आ गया है कि इसी प्रकार के सूचकांक अन्य क्षेत्रों में भी भारतीय वित्तीय एवं आर्थिक संस्थानों द्वारा ही तैयार किए जाने चाहिए, ताकि हम आम नागरिकों को विभिन्न क्षेत्रों में भारत की अतुलनीय प्रगति की वास्तविक जानकारी प्राप्त हो सके।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सुलग रहा देश, इंटरनेट व मोबाइल सेवाएं ठप्प

बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर जारी हिंसक आंदोलन के चलते देश सुलग रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण फैसले के बाद भी छात्र जिद पर अड़े हुए हैं। इस आंदोलन में अब तक 151 लोगों की मौत हो चुकी है। रविवार को 2 घंटे राहत के बाद फिर अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। कई हफ्तों से जारी विरोध प्रदर्शनों के हिंसक रूप लेने के बाद सरकारी नौकरियों से जुड़ी विवादास्पद कोटा प्रणाली को वापस लेने के फैसले से हालात शांत होने के बावजूद इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाएं अब भी ठप्प हैं। ढाका में सड़कों पर सैन्य वाहन तैनात हैं फिर भी प्रदर्शनकारियों का उपद्रव जारी है। कोर्ट ने आरक्षण 54त्न से 7त्न किया, पर मूल मांग नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नौकरियों में आरक्षण 56से घटाकर 7 हो गया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों की दोनों मूल मांगें अधूरी ही है।उनकी पहली मांग थी कि मुक्तिजोधा के परिजनों को मिलने वाली आरक्षण पूरी तरह खत्म हो। कोर्ट के आदेश के बाद भी सबसे ज्यादा आरक्षण उनको ही मिलेगा। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि 94त्न नौकरियां मेरिट से मिले। शेष 6त्न रिजर्व रहें। इनमें से 5त्न महिलाओं और 1त्न दिव्यांगों को मिले। कोर्ट आदेश के बाद 93त्न नौकरियां मेरिट से होगी। छात्रों की दूसरी मांग भी अधूरी रही। छात्रों का आरोप है कि सरकार ने दबाव बनाकर सुप्रीम कोर्ट से फैसला दिलाया है। सरकार ने सोमवार को सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया है और केवल आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी। देश में कुछ दिन पहले ही देखते ही गोली मारने के आदेश के साथ कर्फ्यू लगा दिया गया था और सैन्यकर्मी राजधानी और अन्य क्षेत्रों में गश्त कर रहे थे। भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के समन्वयक हसनत अब्दुल्ला ने बताया कि जिस पूर्ण बंद के आह्वान को उन्होंने पिछले सप्ताह लागू करने का प्रयास किया था उसे अब वापस ले रहे हैं। उन्होंने कहा, लेकिन हम 'डिजिटल कार्रवाई% को रोकने और इंटरनेट सेवाएं बहाल करने के लिए 48 घंटे की चेतावनी जारी कर रहे हैं। अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि वे चाहते हैं कि सरकार कर्फ्यू समाप्त करे और यह सुनिश्चित करे कि देश दो दिनों के भीतर सामान्य स्थिति में वापस आ जाए। जनवरी में हुए आम चुनाव में प्रधानमंत्री शेख हसीना की लगातार चौथी बार जीत के बाद हो रहे इन विरोध प्रदर्शनों ने बांग्लादेश की सरकार के लिए सबसे गंभीर चुनौती पेश की। इस दौरान विश्वविद्यालयों को बंद करने के साथ इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई और सरकार ने लोगों को घर पर रहने का आदेश जारी किया। प्रदर्शनकारियों ने तर्क दिया था कि आरक्षण प्रणाली भेदभावपूर्ण थी और इससे शेख हसीना के समर्थकों को फायदा हुआ।

झरने के पानी में गलती से गिरा शख्स, पल में गलकर गायब हो गया शरीर, वीडियो बनाती रह गई बहन

न्यूयार्क। एडवेंचर के लिए कई लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं और कई बार उनका यह जुनून उनकी जान पर भी भारी पड़ जाता है। ऐसा ही एक मामला अमेरिका से सामने आया था, जब एक लड़का अपनी बहन के साथ तैराकी के लिए अवैध तरीके से येलोस्टोन नेशनल पार्क में चला गया। उस दौरान वो गलती से उबलते हुए पानी में गिर गया और देखते ही देखते उसकी मौत हो गई। हैरत की बात ये थी कि पूरे घटना का वीडियो उसकी बहन ने कैद कर लिया था यूं तो ये घटना साल 2016 की है लेकिन हाल ही में इसकी फाइनल रिपोर्ट आई जिसमें पूरे घटना का जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के रहने वाले कोलिन स्कॉट अपनी बहन सैबल के साथ तैराकी के लिए कोई जगह तलाश रहे थे। ऐसे में ये दोनों भाई-बहन अवैध तरीके से येलोस्टोन नेशनल पार्क के उस एरिया में चले गए, जहां पर जाना प्रतिबंधित था. वहां बोर्डवॉक पर साफ-साफ खतरे का निर्देश भी लिखा हुआ था. चेतावनी वाले बोर्ड को पढ़ने के बावजूद ये लोग आगे बढ़ते चले गए। इस दौरान ये लोग वीडियो भी बना रहे थे. जब बोर्डवॉक से ये दोनों उतर रहे थे, तभी कॉलिन का पैर फिसल गया और वो सीधे खौलते पानी के झरने में जा गिरा और झरने का पानी अम्लीय होने के साथ-साथ खौल रहा था, ऐसे में कॉलिन की तुरंत मौत हो गई और कुछ पल में उसकी बॉडी गल कर गायब हो गई। घटना 2016 की है जिसकी रिपोर्ट अब सामने आई है। उसकी बहन उस वक्त स्मार्टफोन पर वीडियो बना रही थी और जब वह फिसलकर पूल में गिरा तो ये खौफनाक पल रिकॉर्ड हो गया। सैबल अपने भाई को बचाने का प्रयास भी करती नजर आई और तुरंत भागकर पार्क के रेंजर्स के पास गई। जब वो वापस लौटी तो काफी देर हो चुकी थी। उस दौरान सिर्फ कोलिन का सिर, ऊपरी हिस्सा और हाथ के थोड़े हिस्से नजर आ रहे थे। ऐसे में उसे तुरंत ही मृत मान लिया गया। अमेरिकी पार्क रेंजर फिल स्ट्रेले ने एक अलग रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने एक वी-गर्दन वाली टी-शर्ट देखी थी और उसके चेहरे पर एक क्रॉस जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। उसी दौरान तूफान भी आ गया था, जिससे कॉलिन के शव को तुरंत बाहर नहीं निकाला गया लेकिन अगले दिन वहां सिर्फ कॉलिन का बटुआ और चप्पल ही मिले शरीर पूरी तरह गलकर गायब हो गया। रिपोर्ट के अनुसार चूकि झरने का पानी बहुत ज्यादा गर्म और अम्लीय था, जिसकी वजह से कॉलिन का शरीर उसमें घुल गया। अगर उसकी बॉडी रात में निकाल ली गई होती थी, शव बरामद हो सकता था। बता दें कि आमतौर पर बेसिन का पानी 199 डिग्री फारेनहाइट (लगभग 93 डिग्री सेल्सियस) होता है, लेकिन शव को बाहर निकालने के दौरान उसका तापमान 212 डिग्री फारेनहाइट (100 डिग्री सेल्सियस) था. सैबल द्वारा बनाए गए वीडियो को पुलिस ने जारी नहीं किया और सुरक्षित रख लिया।

सुरक्षाबलों ने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम, एक जवान घायल

जम्मू-कश्मीर के बट्टल सेक्टर में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। सुबह तीन बजे घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को सुरक्षाबलों ने घेर लिया। उन्होंने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हुई है। जिसमें एक जवान घायल हो गया है। फिलहाल, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू-कश्मीर के राजोरी जिले में आतंकियों ने एक सुरक्षा चौकी और एक ग्राम रक्षा गार्ड (वीडीजी) के घर पर हमला बोल दिया। सोमवार को हुए हमले में वीडीजी के परिवार के एक सदस्य और एक जवान घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में सेना के जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया, लेकिन उसका शव अभी बरामद नहीं हो सका है। बाकी के आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने पैरा कमांडो के साथ इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया है। अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों ने जिले के गुंदा ख्वास इलाके में शौर्य चक्र से सम्मानित ग्राम रक्षा गार्ड पुरुषोत्तम कुमार के घर पर सोमवार तड़के 3-10 बजे हमला किया। आतंकियों ने फायरिंग और एक ग्रेनेड फेंका। ग्रेनेड पशुशाला के पास फटा, जिससे एक गाय की मौत हो गई। आतंकियों की फायरिंग में पुरुषोत्तम के चाचा विजय कुमार और सेना का एक घायल हो गया। पुरुषोत्तम ने कुछ महीने पहले रियासी में एक आतंकी को मार गिराया था। इसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में उन्हें इसी पांच जुलाई को शौर्य चक्र से सम्मानित किया था। उनके अन्य परिजन गुंदा ख्वास गांव में ही रहते हैं। वीडीजी के घर के बाहर स्थापित सेना की सुरक्षा पोस्ट पर तैनात जवानों के साथ ही पुलिस और खुद वीडीजी ने तुरंत मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी।

गुम हुए 24 साल के यह भारतीय युवा क्रिकेटर कभी होती थी सचिन-सहवाग से तुलना

नेशनल डेस्क। भारतीय क्रिकेट टीम का यह समय फॉर्म में होने का बेहतरीन सबूत है। जून में रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता है। इसके बाद शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को उसी के घर में हुए 5 मैचों की टी20 सीरीज में 4-1 से हराया। अब भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर है, जिसके लिए स्क्वॉड भी घोषित कर दिया गया है, लेकिन इस दौरान एक बहुत बड़ी खबर है, जो पृथ्वी शॉ के करियर को लेकर है। पृथ्वी शॉ ने क्रिकेट की दुनिया में अपनी रहनुमाई बड़ी ही तेजी से बनाई, लेकिन उनका करियर इसी तेजी से भी उतार-चढ़ाव में रहा है। किसी टाइम पर इनकी तुलना मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग से भी जाती थी। मगर अब ये 24 साल का युवा स्टार कहीं गुम हो गया है। कम उम्र में सफलता पाने वाले इस प्लेयर ने साल 2013 में उन्होंने मुंबई के एक क्लब मैच में 500 से ज्यादा रनों की पारी खेली थी। जिसके बाद उनकी कैप्टेंसी में टीम इंडिया ने अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता था। टीम इंडिया आने के बाद लगातार अंदर-बाहर होते रहे। पर शायद अब लगता है कि पृथ्वी शॉ परमानेंट ही भारतीय टीम से बाहर हो गए है। उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला 25 जुलाई 2021 को खेला था। यह उनका टी20 इंटरनेशनल का डेब्यू मैच भी रहा। यानि पृथ्वी शॉ को अपना टी20 इंटरनेशनल का डेब्यू मैच खेलने के बाद किसी भी फॉर्मेट के लिए टीम में जगह ही नहीं मिली। श्रीलंका के खिलाफ खेले गए इस डेब्यू टी20 मैच में पृथ्वी शॉ खाता भी नहीं खोल सके थे। वो पहली ही बॉल पर गोल्डन डक के साथ आउट हुए थे। पृथ्वी शॉ ने अपने करियर की शुरुआत वेस्टइंडीज के खिलाफ राजकोट टेस्ट में एक धमाकेदार शतक के साथ की थी, जो उनकी क्रिकेट क्षमता की प्रशंसा का केंद्र बन गया। अक्टूबर 2018 में हुए इस मैच में पृथ्वी शॉ ने पहली ही इनिंग में 134 रनों की शतकीय पारी खेलकर धमाकेदार शुरुआत की लेकिन उनके करियर में विवाद भी उसी तरह से सामाजिक मीडिया पर छाए रहे, जैसे कि डोपिंग टेस्ट में फेल होना और बैन का सामना करना। इसके बाद पृथ्वी शॉ चोटिल हो गए और टीम से बाहर हो गए। उनके अंतराल में कई दौरों में उन्हें टीम से हटाया गया, जिससे उनकी वापसी मुश्किल बन गई। वे कई अवसरों पर अच्छे प्रदर्शन करते दिखे, लेकिन उनकी स्थिति मजबूत नहीं रही। घरेलू क्रिकेट और ढ्ढक्क में भी उन्होंने अपने प्रदर्शन से टीम में अपनी जगह बनाने का प्रयास किया, लेकिन इसमें सफलता हासिल नहीं की। कोरोनाकाल के दौरान मई 2021 में लॉकडाउन लगा हुआ था। उसी बीच पृथ्वी शॉ को गोवा में छुट्टी मनाने का मन हुआ और वो कार लेकर कोल्हापुर के रास्ते गोवा के लिए निकल पड़े थे। तब उन पर नियमों के उल्लंघन का भी आरोप लगा था, क्योंकि वो बगैर ई-पास के निकले थे। इस कारण उनको महाराष्ट्र के अंबोली में पुलिस ने रोक लिया, तब पृथ्वी शॉ ने अधिकारियों से उन्हें जाने देने की अपील की, लेकिन वे नहीं माने। करीब एक घंटे के इंतजार के बाद पृथ्वी शॉ ने मोबाइल के जरिए ई-पास के लिए अप्लाई किया, जिसके बाद उन्हें गोवा जाने की अनुमति मिली। वे क्रिकेट की दुनिया में एक नई उम्मीद थे, जिनकी उम्मीदें उच्च थीं, लेकिन अनियमितताओं और विवादों ने उनकी क्रिकेट करियर की राह में कई बाधाएं डाल दीं। वे सामाजिक मीडिया और मीडिया में अक्सर चर्चा में रहे, लेकिन उनके प्रदर्शन में निरंतरता की कमी उनकी बड़ी समस्या बन गई। पृथ्वी शॉ के करियर की इस दौरानी सफलता और विवादों का संघर्ष उनके क्रिकेट करियर की अनूठी कहानी है। वे अपनी क्षमता और उम्मीदों से उच्चाईयों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने आए चुनौतियों ने उनकी प्रगति में विघ्न डाला। उन्हें इस संघर्ष से बाहर आकर अपनी क्रिकेट करियर को नई दिशा देने का समय आया है।

किसान आंदोलन 2.0 की आहट

संयुक्त किसान मोर्चा का दिल्ली कूच का एलान, 15 अगस्त को करेंगे ट्रैक्टर रैली

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी समेत 12 पुरानी मांगों पर संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने नए सिरे से किसान आंदोलन 2.0 की रणनीति बनाई है। नई रणनीति के तहत एक अगस्त से 22 सितंबर तक एसकेएम पूरे देश में कई विरोध कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। संगठन ने किसानों के दिल्ली कूच का आह्वान करते हुए तीन साल पहले गणतंत्र दिवस की तरह इस बार स्वतंत्रता दिवस पर ट्रैक्टर रैली का आयोजन करने और तीन नए आपराधिक कानूनों की प्रतियां जलाने की घोषणा की है। राजधानी के कांस्टिट्यूशन क्लब में बैठक के बाद एसकेएम ने एक अगस्त को राजधानी समेत देशभर के जिला मुख्यालयों में सरकार की अर्थी यात्रा निकालने की घोषणा की है। संगठन ने देशभर के किसानों का हरियाणा सीमा पर आंदोलनरत किसानों के समर्थन में दिल्ली कूच करने का आह्वान किया है। किसान आंदोलन के 200 दिन पूरा होने के मौके पर 31 अगस्त को किसानों का शंभू सीमा समेत अन्य सीमाओं पर दिल्ली कूच के लिए जुटने का आह्वान किया गया है। आंदोलन के दूसरे पड़ाव में एसकेएम ने हरियाणा और यूपी में तीन रैलियां आयोजित करने की घोषणा की है। इसके तहत हरियाणा के जिंद और पीपली में 15 और 22 सितंबर जबकि यूपी के संभल में एक सितंबर को रैली का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि हरियाणा में अक्तूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। सरकार पर छल करने का आरोप- एसकेएम ने सरकार पर छल करने का आरोप लगाते हुए आरपार की जंग की घोषणा की है। गौरतलब है कि किसान एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने, आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लेने, इस दौरान जिन किसानों का निधन हुआ उनकी स्मृति में स्मारक बनाने, तीनों आपराधिक कानून वापस लेने, विश्व व्यापार संगठन से नाता तोडने की मांग कर रहे हैं।

वन महकमा छीनने से अपनाए बगावती तेवर, दी चेतावनी

मंत्री नागर सिंह चौहान छोड़ेंगे पद, पत्नी भी देगी सांसदी से इस्तीफा

भोपाल। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान वन महकमा छीने जाने से नाराज हो गए हैं। उन्होंने बगावती तेवर अपना लिए हैं और मंत्री पद से इस्तीफा देने की धमकी भी दे दी है। वह तो यह भी कह गए कि यदि उनकी बात को सुना नहीं गया तो झाबुआ-रतलाम संसदीय सीट से सांसद अनिता नागर सिंह चौहान भी अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। मोहन यादव सरकार में मंत्री बनने के बाद नागर सिंह चौहान के पास तीन विभाग थे। रविवार को रामनिवास रावत को वन एवं पर्यावरण विभाग दे दिए। इससे नागर सिंह चौहान नाराज हो गए। उनके पास इस समय सिर्फ अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ही बचा है। कैबिनेट में इसे उनका कद घटने के रूप में देखा जा रहा है। नागर सिंह चौहान की पत्नी अनिता नागर सिंह चौहान झाबुआ-रतलाम सीट से लोकसभा सदस्य हैं। सोमवार से ही संसद में बजट सत्र शुरू हुआ है, जिसमें सभी सांसदों को भाग लेना था। अनिता नागर सिंह चौहान भी दिल्ली जाने वाली थी। हालांकि, रविवार के घटनाक्रम के बाद वह दिल्ली नहीं गई और उन्हें रोक लिया गया। नागर सिंह चौहान का कहना है कि यदि उनका कोई विभाग छीना जाना था तो उन्हें बताया भी जा सकता था। उनका विभाग छीनकर कांग्रेस से आए हुए नेता को देना गलत है। यह फैसला अचानक हुआ और उनसे वन एवं पर्यावरण विभाग छीन लिया गया। वह पार्टी फोरम पर अपनी बात रखेंगे। सूत्रों का कहना है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के सामने वह अपनी बात रख चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि समस्या का समाधान नहीं निकाला गया तो उनकी पत्नी अनिता नागर सिंह चौहान भी सांसदी छोड़ देंगी।

विभाग छीनकर कांग्रेस से आए हुए नेता को सौंप देने से मैं दुखी हूं

मीडिया से फोन पर हुई बातचीत में चौहान ने कहा कि अलीराजपुर को कांग्रेस का अभेद्य गढ़ माना जाता था। वहां हम कांग्रेस से लगातार लड़ रहे हैं। लगातार चुनाव जीतने के बाद मध्य प्रदेश सरकार में आलीराजपुर जिले को पहली बार मंत्री बनने का अवसर मिला था। सात महीने बाद बिना पूछे, बिना चर्चा किए मेरे दो विभाग को कांग्रेस से आए हुए मंत्री रामनिवास रावत को दिए हैं। इससे मैं बहुत दुखी हूं। हम भाजपा के मूल कार्यकर्ता हैं। पूरे मध्य प्रदेश में बरसों बरस से कार्यकर्ता भारतीय जनसंघ के जमाने से संघर्ष करते आए हैं। मेरे जैसे कार्यकर्ता से विभाग छीनकर कांग्रेस से आए हुए नेता को सौंप देने से मैं दुखी हूं। मुझे लगता है कि इस पद पर नहीं रहना चाहिए। हालांकि, अमर उजाला ने उनसे बात कर यह जानने की कोशिश की कि क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो वे बोले कि फिलहाल मैं मीटिंग में हूं। आपसे बाद में बात करता हूं।

वो बातचीत नहीं करेंगे तो नो प्रॉब्लम - मंत्री

मंत्री ने दावा किया कि उन्होंने इस मुद्दे पर रविवार की रात को पार्टी नेताओं से बातचीत की है और योजना बनाई है कि आगे भी बातचीत जारी रहेगी। नागर सिंह चौहान ने कहा, ह्यअगर वो चाहेंगे तो मैं उनसे बात करूंगा। अगर वो नहीं चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम। आपको बता दें कि रामनिवास रावत श्योपुर जिले के विजयपुर विधानसभा सीट से छह बार के विधायक रहे हैं। वो हाथ के साथ थे मगर लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था। 8 जुलाई को उन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी। रविवार को राज्य सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया गया था कि रामनिवास रावत अब वन और पर्यावरण विभाग के मंत्री होंगे।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक श्रीमती ज्योती मिश्रा द्वारा कॉम्पेक प्रिंटर्स प्रा. लि. फ्री प्रेस हाउस 3/54, प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 45ए गुप्ता चैम्बर पहली मंजिल जावरा कंपाउंड इंदौर, (म.प्र.) से प्रकाशित।
प्रधान सम्पादक : अशीष मिश्रा आर.एन.आई. पंजीयन क्रमांक : एमपी/एच/आइएन 2009/34385 फोन नं : 0731-4202569 फैक्स नं : 0731-4202569